सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 164, नई दिल्ली, शुक्रवार 22 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिले भी झुका करती है।

03 राजा इकबाल सिंह डमी मेयर हैं, उनमें अपने ही पार्षद की शिकायत...
06 आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को प्राथमिकता
08 डिप्टी कमिश्नर द्वारा अवैध रूप से निजी जानकारी एकत्र करने वाले व्यक्तियों को चेतावनी

भारत सरकार, राज्य सरकारो के साथ जनता को अरबों रुपयों का चूना लगाने वालो के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर भी गृह मंत्रालय क्यों है चुप ?

पिंकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

- दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभक्त से करोड़ों का वाहन स्क्रैपिंग घोटाला
- सरकारी विभाग के आला अधिकारी, प्रवर्तन एजेंसियां और स्क्रैपर्स जांच के घेरे में

शांति सेवा न्याय
DELHI TRAFFIC POLICE
WITH YOU FOR YOU ALWAYS

दिल्ली नगर निगम
MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
तमसो मा ज्योतिर्गमय

सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

दिल्ली में जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों (ईएलवी) के निपटान में करोड़ों रुपये का विशाल घोटाला जग जाहिर है।

प्रवर्तन एजेंसियों (दिल्ली परिवहन विभाग प्रवर्तन शाखा, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम प्रवर्तन शाखा) और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) के बीच गहरी मिलीभगत का संदेह स्पष्ट नजर आ रहा है।

जाली प्रमाणपत्रों, ज़ब्त किए गए वाहनों के अनियमित निपटान और सरकारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन से जुड़े इस घोटाले से कथित तौर पर सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है।

यह विवाद उस दिन से दिल्ली में शुरू हो गया था जिस दिन से दिल्ली परिवहन विभाग ने एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया के आदेश को मानने की बात कह दिल्ली में 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 साल पूरे हो चुके अन्य फ्यूल मोड से चलने वाले वाहनों को उठवाकर दिल्ली से बाहर पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द करना शुरू किया था। इस कार्यवाही से रूष्ट होकर जनता दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने लगी और अनगिनत शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली परिवहन विभाग को इसके लिए एक नीति बनाने और उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश जारी करना पड़ा, जिस कारण दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा 20 फ़रवरी, 2024 वाहन स्क्रैप नीति घोषित की। परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर जारी इस नीति का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों को लागू करना था जिनमें 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य है।

दिशानिर्देशों में स्पष्ट प्रावधान दिए गए: पैनलबद्ध आरवीएसएफ में स्क्रैपिंग का समान वितरण, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रियाएँ, और सरकारी खातों में बिना दावे वाले स्क्रैप मूल्य को अनिवार्य रूप से जमा करना।

इसके अलावा सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 18 अक्टूबर, 2024 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के तहत सरकारी ज़ब्त वाहनों के लिए जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) पर प्रोत्साहनों पर स्पष्ट रूप से रोक और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह साफ नजर आता है की कई आरवीएसएफ एवम्-प्रवर्तन अधिकारियों ने मिलीभगत करके ज़ब्त किए गए वाहनों के बदले जाली जमा प्रमाणपत्र जारी कर उसके द्वारा प्रोत्साहन राशि प्राप्त की जो की अधिसूचना का सीधा उल्लंघन के साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों के राजस्व में चुना लगाने का सबूत है।

अधिसूचना के अनुसार वाहन स्क्रैप सीओडी केवल उन वाहन मालिकों को जारी हो सकती हैं जो स्वेच्छा से अपने वाहनों को स्क्रैप करते हैं, जिससे उन्हें नए वाहन खरीदते समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि का फायदा उपलब्ध हो सके। ज़ब्त किए गए वाहनों पर अवैध रूप से सीओडी जारी करके, स्क्रैपिंग कंपनियों ने सार्वजनिक धन की हेराफेरी की।

जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार

1. एसजी जंकयार्ड एंड रीसाइक्लिंग एलएलपी
2. पीकेएन मोटर्स
3. भारत व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी
4. गो ग्रीन ईएलवी हैंडलर्स
5. ग्रांड ग्लोबल जंकयार्ड एंड रीसाइक्लिंग एलएलपी
6. सरल ऑटो स्क्रैपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7. सेवन स्टार ऑटो स्क्रैपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8. सलेक्ट आटो एवम्-अन्य कई स्क्रैप डीलरो ने ना तो कारण बताओ नोटिस के बाद विभागों में पैसे जमा कराए और स्पष्ट प्रतिबंधों के बावजूद अवैध सीओडी जारी किए जिनकी जांच करना बहुत ही आसान है पर फिर भी विभाग एवम्-दिल्ली सरकार है चुप

दिल्ली परिवहन विभाग में तीन पहिया तीन सवारी के लिए अनिवार्य वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट की जांच में पाया गया की परिवहन विभाग के अधिकारी ने बिना प्रमाणपत्र की जांच किए नए तीन पहिया तीन सवारी वाहनो को खरीदने के आदेश जारी कर दिए, जब की सच्चाई यह है की वह वाहन स्क्रैप हुए ही नहीं हैं और स्क्रैप डीलर द्वारा जारी प्रमाणपत्र (सीओडी) पर डिजिटल हस्ताक्षर किए ही नहीं गए थे और डिजिटल हस्ताक्षर किए बिना वाहन पोर्टल पर वाहन स्क्रैप होना संभव ही नहीं है, अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के साथ विभाग द्वारा जारी एसओपी का खुला उल्लंघन पूरी जानकारी परिवहन आयुक्त को होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हज़ारों ज़ब्त वाहनों का निबटान कानूनी प्रक्रिया से करने की जगह प्रवर्तन शाखा एवम् विभाग के आला अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए, वाहनों को सीधे आरवीएसएफ को सौंप दिया जिस कारण सरकारी राजस्व में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।

स्क्रैपिंग नीति के खंड 10(iii) के अनुसार, यदि 15 दिनों के भीतर वाहन मालिकों द्वारा स्क्रैप मूल्य के प्रति दावा नहीं किया जाता है, तो आरवीएसएफ को स्क्रैप की राशि सरकारी खातों में जमा करनी होगी। फिर भी अधिकतर आरवीएसएफ कंपनियों ने विभागों में भुगतान नहीं किया और विभागों द्वारा जब कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तो भी बिना किसी वसूली कार्रवाई के नज़र अंदाज़ कर दिया गया।

यह घोटाला चुनिंदा दंडात्मक कार्रवाई को भी उजागर करता है। महिंद्रा एमएसटीएस री-साइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक उल्लंघन के लिए काली सूची में डाल दिया गया जबकि गो ग्रीन ईएलवी हैंडलर्स, जिसे विस्फोटक अधिनियम के तहत एक केस प्रॉपर्टी वाहन को कबाड़ करते हुए पकड़ा गया था उसको विभाग ने काली सूची में शामिल करने की जगह उससे बेरोकटोक अपना कारोबार जारी रखा। चोरी के वाहनों के साथ पकड़े जाने के बाद भी एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित आरवीएसएफ कंपनियों को प्रवेश देकर उनके साथ कारोबार किया।

विभागों द्वारा अनियमितताओं में और इजाफा करते हुए मोटर वाहन नियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के दायरे में न आने वाले 10,900 से ज़्यादा ई-रिक्शा को पदों की शक्ति का दुरूपयोग करते हुए उठवाकर सीधे आरवीएसएफ को स्क्रैप करने के लिए सुपुर्द कर दिए जिससे गरीब मालिकों की आजीविका छिन गई।

आरवीएसएफ कंपनियों द्वारा अपने निजी कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस और एमसीडी के लोगो वाले फर्जी पहचान पत्र तक जारी कर रखे थे।

सीबीआई जांच की मांग जाली प्रमाणपत्र, बकाया राशि की वसूली न होना, फर्जी चालान, अनियमित निपटान और प्रोत्साहनों का दुरुपयोग जैसे उल्लंघनों का विशाल दायरा प्रवर्तन एजेंसियों और स्क्रैपिंग फर्मों के बीच एक व्यवस्थित सांठगांठ की ओर इशारा करता है।

जनहित के खिलाफ और राजस्व को चुना लगाने वालो को सही सजा दिलाने के उद्देश्य से इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने वाहनों को गलत तरीके से स्क्रैप किया गया, कितनी नकली सीओडी बना कर उस के द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि का फायदा उठाया और कितना सार्वजनिक धन गबन किया गया। इसके अतिरिक्त किन अधिकारियों को इस कार्य में फायदा हुआ।

पर्यावरण अनुपालन की आड़ में संचालित इस कथित घोटाले ने एक हरित पहल को चुनिंदा कंपनियों और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए नकदी का साधन बना दिया है, जिससे दिल्ली में जवाबदेही और शासन व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।

क्या जनता की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली की सड़कों पर चलवाए जा रहे हैं अनाधिकृत वाहन, बड़ा सवाल ?

पिंकी कुंडू, सह - संपादक परिवहन विशेष के द्वारा

- क्या जनता की सुरक्षा, सुविधा और सुखद सार्वजनिक सेवा के प्रति सरकार और विभाग की देन हैं यह अनाधिकृत वाहन ?
- कौन है इनको दिल्ली की सड़को पर खुले आम बेखौफ चलवाने में मददगार ?

नईदिल्ली। सभी इस बात से परिचित है की दिल्ली में पूर्व में रही आम आदमी पार्टी सरकार और तत्काल में तख्त संभाल रही भाजपा सरकार जनता को सार्वजनिक सवारी वाहन सेवा उपलब्ध करवाने में पूरी तरह नाकाम रही है।

राज्य में जनता की जरूरत अनुसार सार्वजनिक सवारी वाहन सेवा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का पहला दायित्व है।

दिल्ली में जनता को सुरक्षित समयानुसार सार्वजनिक सवारी वाहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम का गठन किया गया था पर पिछले 14 सालों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को एक भी वाहन ना तो खरीदने दिया और ना ही खरीद कर दिया।

भारत देश में सड़को पर चलने के लिए किसी भी वाहन की अधिकतम आयु 15 वर्ष घोषित है और उसके बाद उसे स्क्रैप करना आवश्यक हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जो सार्वजनिक सवारी वाहन उपलब्ध रहने चाहिए उन्हें जानबूझ कर पिछले 14 सालों से नहीं करवाया अर्थात दिल्ली सरकार ने जान बूझकर दिल्ली की जनता को अनाधिकृत/ गैर कानूनी तरीके से चलने वाले सवारी वाहनों पर सफर करने की और धकेला और यही कारण है की दिल्ली की सड़को पर अनाधिकृत रूप से चल रहे सार्वजनिक सवारी सेवा में वाहनों पर कोई कार्यवाही प्रवर्तन शाखाओं (दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस) द्वारा नहीं करने का। दूसरे शब्दों में कहे तो उनके खिलाफ दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग कार्यवाही नहीं चाहते।

दिल्ली में बढ़ते हुए महिलाओं से वाहनों में छेड़खानी और लूटपाट के मामलों का भी मुख्य कारण अनाधिकृत वाहनों का सड़को पर चलना है पर राज्य सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनकी ही गलतियों का परिणाम है यह जो जनता को झेलना पड़ रहा है।

1. दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में सड़को पर चले जाए आपको वहां बाहरी निजी नंबरों के वाहन सवारी बिठाते और उतारते साफ नजर आ जाएंगे पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस को वहां उपस्थित रहते हुए भी यह वाहन नजर नही आते।
2. दिल्ली की सड़को पर "**बिना पंजीकरण**" के वाहन खुले आम सवारियों को बैठाते और उतारते नजर आ जाएंगे पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस को वहां उपस्थित रहते हुए भी बिना पंजीकरण के चलते वाहन नजर नही आते।

आप की जानकारी हेतु बता दें मोटर वाहन नियम के अनुसार बिना पंजीकरण वाहन सड़को पर चल नहीं सकते और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित है की बिना पंजीकरण का वाहन दिल्ली की सड़को पर सवारी सेवा में चलता नहीं पाया जाना चाहिए। इसके बावजूद दिल्ली की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सड़कों पर 24 घंटे आप बिना पंजीकरण के वाहनों को व्यवसायिक गतिविधि में शामिल देख सकते हैं।

अब आप ही बताए गैर कानूनी वाहन व्यावसायिक गतिविधियों में कार्य करते हुए सब को दिख रहे है पर दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली पुलिस को नजर नहीं आ रहे, आखिर क्या कारण है जिनके कारण जनता असुरक्षित होते हुए भी इनका प्रयोग करने पर मजबूर हैं।

दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग को तत्काल प्रभाव से जनहित और जन सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की सड़को पर बेखौफ दौड़ रहे अनाधिकृत वाहनों को हटाना और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

निजी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ट्रक मालिकों पर गुंडागर्दी और माननीय न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन

वित्तीय मामलों में भेदभाव बंद की जाए,
एनसीएलटी के तर्ज पर गाड़ी मालिकों के ऋण भी माफ किए जाएं –
आजाद देश में गुलामों की तरह व्यवहार अब और नहीं

नई दिल्ली -राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने आज निजी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ट्रक मालिकों और संचालकों के साथ की जा रही गुंडागर्दी और न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। देशभर में ट्रक मालिकों, चालकों व ट्रांसपोर्टरों की यूनियन के आवाज के रूप में काम करने वाला हमारा मोर्चा इस मुद्दे पर तथ्यात्मक आधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहना चाहता है कि ऋण वसूली के नाम पर अवैध तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो ट्रक मालिक और ट्रांसपोर्ट उद्योग को बर्बाद कर रहे हैं।

ट्रक संचालक, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, अक्सर निजी बैंक और एनबीएफसी के घातक हथियारों से लैस बीच सड़क पर रिकवरी एजेंट्स द्वारा धमकी, मारपीट, प्रताड़ना और जबरन वाहन जब्ती का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के फैसलों के बावजूद, ये संस्थाएं आरबीआई की गाइडलाइंस और कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना लगातार कर रही हैं। उदाहरणतः सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फैसले में एक निजी बैंक के मामले में रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी पर रोक लगाई गई थी, जहां कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार को धमकाना या बल प्रयोग अवैध है।

पटना हाई कोर्ट के 2023 के फैसले में बिना कोर्ट ऑर्डर के वाहन जब्ती पर 50,000 रुपये का जुर्माना और एफआईआर का प्रावधान किया गया।

हालिया मामलों में, जैसे कि हरियाणा के कैथल व अन्य मामलों में में ट्रक मालिकों व ट्रांसपोर्टर्स पर हो रहे अत्याचार, जहां एजेंट्स द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें बढ़ रही हैं।इसी तरह, राजस्थान के हनुमानगढ़ में ट्रक संचालकों की बैठक में विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई, जहां रिकवरी एजेंट्स के गुंडागर्दी एक प्रमुख मुद्दा के रूप में छाया रहा।

डॉ. राजकुमार यादव ने कहा, ₹हम लोग संपूर्ण राष्ट्र में हमारी जुझारू, ईमानदार व लगनशील टीम के साथ ट्रक संचालकों के मान-सम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं।निजी फाइनेंसरों की यह गुंडागर्दी ट्रक ऑनरों के भविष्य को प्रभावित कर अंधकार में धकेल रही है, जैसा कि हमारी प्रांतीय बैठकों में सामने आया है। उड़ीसा के राउरकेला, क्योझर, सुंदरगढ़, जोड़ा,तालचेर, अंगुल, झारसुगुड़ा मेँ लौह अयस्क व कोयले की ढूलाई करने वाले ट्रक ऑनर्स की भुगतान लंबित रहने के कारण एक आध किश्ती टूट जाने पर भी बिना नियम के ही हथियारों के बल पर रिकवरी एजेंट्स के द्वारा गाड़ियां जबरन जब्त कर ली जाती है व बिना किसी दिशा निर्देश के पालन करते हुए गाड़ियों की नीलामी आम बात है।सरकार और आरबीआई को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे।₹

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की मांग है कि ₹दोषी वित्तीय संस्थाओं और उनके एजेंट्स पर तत्काल एफआईआर दर्ज हों और सख्त कार्रवाई के आदेश निर्गत किए जाएं 1 ट्रक मालिकों के लिए सीधे आरबीआई द्वारा विशेष हेल्पलाइन और कानूनी सहायता केंद्र की स्थापना हो 1 आरबीआई गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट और निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान की जाए।

किसी भी सूरत में प्राकृतिक आपदा या हड़ताल वाले महीने की किस्त को आगे बढ़ाने के प्रावधान को लागू किया जाए 1 एनसीएलटी के तर्ज पर गाड़ी मालिकों के ऊपर बकाए किस्त व कर्ज को 10% से 20% वसूली कर ऋण समाप्त करते हुए गाड़ियों का हस्तांतरण सुनिश्चित हो"

-"गाड़ी मालिकों के ऊपर निजी वित्तीय कंपनियां/ बैंकों, एनबीएफसी एवं बैंकों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ अंतिम पंक्ति पर खड़े गाड़ी मालिकों व ट्रांसपोर्टर के साथ संघर्ष के लिए "उफ्तत्सा -" राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) जिम्मेदारी पूर्ण डटे रहकर अपनी भूमिका का नीस्वार्थ पूर्वक निर्वहन करेगी "

पोला पिठोरी कुशाग्रहणी अमावस्या आज

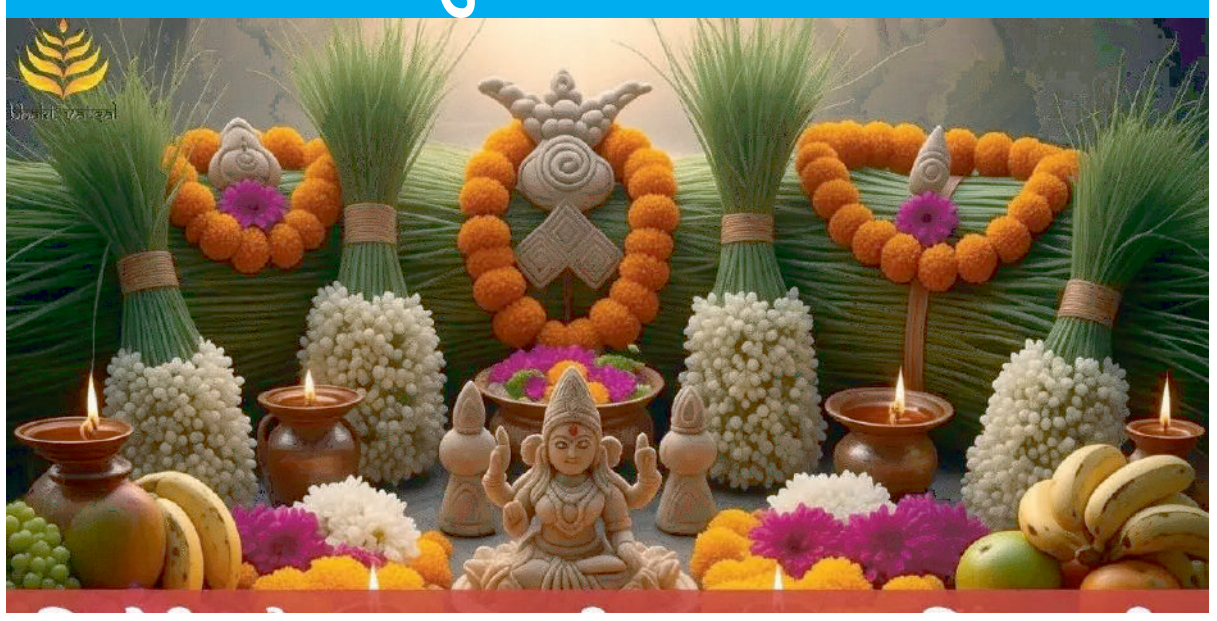

पिठोरी अमावस्या भाद्रपद मास में आती है। पितृ पूजन, दान-पुण्य के लिए इसका विशेष महत्व है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि पर आने वाली पिठोरी अमावस्या देशभर में मनाई जाती है। ये उत्तर भारत में कुशाग्रहणी अमावस्या के तौर पर मनाई जाती है। इसके साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी महत्व है।

पिठोरी अमावस्या कब है?

==========

भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 22 अगस्त को दोपहर 11.57 बजे लगेगी और 23 अगस्त को 11.37 बजे पूरी होगी। 22 अगस्त को अमावस्या मध्यकाल में लग रही है और उदया तिथि नहीं है, ऐसे में इस दिन पिठोरी अमावस्या मान्य होगी। इस दिन पितृ पूजन, तर्पण, श्राद्ध आदि का महत्व है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद भी मिलता है।

कुशाग्रहणी अमावस्या कब है?

==========

इसी तरह 23 अगस्त को सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि लग रही है। ऐसे में इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पितरों के नाम पर जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं। 23 अगस्त की अमावस्या तिथि को कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन कुश इकट्ठा करने का महत्व है। इस दिन जिनके माता या पिता नहीं होते हैं वे कुश इकट्ठा करते हैं और इसे घर पर लाते हैं। यही कुश पूरे साल पितृ पूजन में काम आता है। इसके अलावा साल के अन्य दिनों में कुश नहीं उखाड़ा जाता है।

पिठोरी अमावस्या का महत्व

==========

पिठोरी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने, श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से दुख दर्द दूर होते हैं। आपकी बाधाएं दूर होती हैं। शनिदेव की पूजा करने का भी महत्व होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि शनिदेव को समर्पित होती है। वहीं पिठोरी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करने पापों से मुक्ति मिलती है।

64 योगिनियों की पूजा का महत्व

==========

कथाओं के अनुसार, भाद्रपद की पिठोरी अमावस्या पर मां पार्वती ने 64 योगिनियों के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा की थी। दरअसल पिठोरीर शब्द का अर्थ होता है 'आटे की मूर्तियां'. इसलिए इस दिन महिलाएं आटे से 64 योगिनियों की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती हैं। 64 योगिनियां देवी शक्ति का रूप मानी जाती हैं, और उनकी आराधना से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

पिठोरी अमावस्या की पूजन विधि

==========

इस दिन महिलाएं प्रातःकाल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और पूजा की तैयारी करती हैं। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं और फिर पितरों पर जल अर्पित करती हैं। पितरों के लिए जल अर्पित करते समय ₹ॐ पितृभ्यः नमः₹ मंत्र का जाप किया जाता है। पूजा स्थल में घी का दीप जलाकर बच्चों के नाम से व्रत का संकल्प लेती हैं। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से संतान के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। बताते चलें कि दक्षिण भारत में पिठोरी अमावस्या को पोलाला अमावस्या भी कहा जाता है।

कण-कण में राम! भगवान शिव ने पार्वतीजी को बताया सगुण-निर्गुण का रहस्य

सुखी भारती

विचार करने योग्य बात है, कि क्या भगवान शंकर सचमुच देवी पार्वती के इन विचारों से रुष्ट भाव में थे? जी नहीं! वास्तव में वे तो संसार में यह भाव रखना चाह रहे थे, कि भगवान श्रीराम जी, एवं वह परम शक्ति, जिसको वेद भी गाते हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है।

भगवान शंकर देवी पार्वती को भगवान श्रीराम जी के संबंध में विस्तार से कहना आरम्भ करते हैं। वे अभी तक किंचित भी, कहीं भी उनके किसी प्रश्न को रुष्ट भाव से नहीं ले रहे थे। किंतु अब उनके श्रीमुख से यह वाक्य रिस कर बाहर आये-

'एक बात नहिं माहि सोहानी।
जदपि मोह बस कहेहु भवानी।।
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना।
जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना।।'

किंतु हे पार्वती! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं।

विचार करने योग्य बात है, कि क्या भगवान शंकर सचमुच देवी पार्वती के इन विचारों से रुष्ट भाव में थे? जी नहीं! वास्तव में वे तो संसार में यह भाव रखना चाह रहे थे, कि भगवान श्रीराम जी, एवं वह परम शक्ति, जिसको वेद भी गाते हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर कोई दशरथ नंदन श्रीराम जी और सूक्ष्म रुप में, कण-कण में समाई दिव्य परम शक्ति में कोई अंतर मानता है, तो वह महाअभागा है। उसके संबंध में भोलेनाथ कहते हैं-

'कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच।
पाषंडी हरि पद बिमुख जानहिं झूठ न साच।।'

अर्थात जो मोह रुपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखण्डी है, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ-सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं।

जिनको निर्गुण सगुण का रत्ती भर भी ज्ञान या विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढंत बातें बका करते हैं, जो श्रीहरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमिते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है।

भगवान शंकर के यह विचार श्रवण कर, देवी पार्वती कहती हैं, कि हे देव! आप जो कह रहे हैं, वह ही परम सत्य होगा। किंतु मैं अथवा मेरी जैसी ऐसी बुद्धि किसी की हो, तो वह क्या करे-

'अस निज हृदयँ बिचारि तजु संसय भजु राम पद।
सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम।।'

अर्थात हे पार्वती! तुम्हारे पास केवल एक ही राम बाण है, कि तुम केवल और केवल मेरे ही वचनों पर विश्वास करो। क्यों मेरे वचन ऐसे हैं, जैसे अँधकार का नाश करने के लिए, सूर्य के प्रकाश की किरणें होती हैं। लो अब मैं तुम्हें सर्गुण व निर्गुण प्रमात्मा पर विशेष बल देकर समझाता हुँ-

'सगुनिह अगुनहि नहिं कछु भेदा।
गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा।।
अगुन अरुप अलख अज जोई।
भगत प्रेम बस सगुन सो होई।।'

हे पार्वती! मैं सत्य कह रहा हुँ, कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। सभी मुनि, पुराण, पंडित और वेद ऐसा ही भाषण कर रहे हैं। जो निर्गुण अरुप, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है।

साधारण शब्दों में अगर समझाया जाये, तो जल और ओले में क्या भेद है? एक सामान्य व्यक्ति भी बता सकता है, कि बाहर से भले ही जल और ओले की बनावट में भेद है। किंतु भीतर से तो दोनों एक ही हैं। और उनका वह भीतरी रुप है 'जल'। उस जल को जब किसी के हाथों में नहीं बँधना, या नहीं समाना, तो वह जल रुप में तरल ही रहता है। किंतु अगर वह जल सोच ले, कि मुझे अब एक रुप में आकार लेना है, तो वह ओले के रुप में आ जाता है। प्रमात्मा भी ठीक इसी प्रकार है। उसे जब किसी के सथूल प्रभाव में नहीं रहना होता है, तो वह निराकार प्रकाश रुप में रहता है। किंतु जब भक्तों के प्रेम भावों के वश बँधता है, तो अपने प्रकाश रुप से परे होकर, वह देह धारण कर लेता है, और साकार रुप कहलाता है।

देवी पार्वती बड़े ध्यान से भगवान शंकर की सीख सुन रही है।

क्रमशः

- सुखी भारती

अश्वगंधा पाक

अश्वगंधा के बारे में लगभग सभी लोग जानते है और इससे मिलने वाले कुछ एक लाभों के बारे में भी आप लोग परिचित होंगे लेकिन अश्वगंधा के जितने गुण आप जानते है या इसके लाभों की आप जो कल्पना करते है अश्वगंधा के फायदे उससे कहीं अधिक है अश्वगंधा को आयुर्वेद में रसायन की संज्ञा दी गई है यानी एक ऐसा रसायन जो ना केवल शरीर की बहुत सी व्याधियों में कारगर है बल्कि यह शरीर में उम्र के साथ पड़ने वाले प्रभावों को रोकने में बहुत ही शक्तिशाली रसायन है अलग अलग रोगों में इसके विभिन्न द्रव्यों के बने हुए योग शरीर को एक अलग ही अनुभव प्रदान करते है।

अश्वगंधा बलय शक्तिवर्धक और शरीर की धातुओं को पुष्टि करने वाला उत्तम रसायन है वात पित प्रधान रोगों प्रमेह मूत्र विकार धातु रोग कमजोरी आदि में अश्वगंधा का प्रयोग हमेशा से किया जाता रहा है आयुर्वेद के सैंकड़ो योगों में इसका प्रयोग प्रधान औषधि या सहायक औषधि में किया जाता है।

आज की पोस्ट में हम जाएंगे अश्वगंधा पाक बनाने के बारे में जिसका सेवन बलवर्धक पुष्टिवर्धक होता है दिमागी कार्य करने वाले लोगो और बच्चो के लिए यह बहुत उपयोगी रसायन है। जो लोग हमेशा थके थके से रहते है आलस्य जिनका पीछा ना छोड़ रहा हो। शरीर में हल्का साधारण दर्द रहता हो उनके लिए अश्वगंधा पाक खास उपयोगी है।

महिलाए जिनका काम करने में मन ना लगता हो स्वभाव बदलता रहता हो गुस्सा चिड़चिड़ा स्वभाव हो उन्हे सुपारी पाक और अश्वगंधा पाक दोनो के सेवन से लाभ होता है। अश्वगंधा पाक धातुओं की पुष्टि करता है वीर्य विकार आदि में खास उपयोगी है। लेकिन इसे केवल इन्हीं विकारों की जड़ी बूटी या दावा मानना अश्वगंधा के पूरे गुणों को छुपाने जैसा है अश्वगंधा बहुत सारी समस्याओं को दूर करने वाली जड़ी बूटी है इसको सम्पूर्ण जानकारी जनमानस तक पहुंचाने से ही लोग सही तरीके से इसके लाभ ले सकते है।

अश्वगंधा पाक बनाने के लिए आवश्यक घटक द्रव्य.....

उत्तम नागौरी अश्वगंधा का पाउडर 250 ग्राम
देशी गाय का दूध 4 लिटर
देशी गाय का घृत 500 ग्राम
मिश्री देशी खांड 1 किलो
सोंठ 100 ग्राम
छोटी पीपल 50 ग्राम
तेजपता, दालचीनी, नागकेशर, काली मिर्च, असली वंशलोचन, इलायची, जायफल, मोचरस, जटामांशी, लौंग, पीपलामुल, गोखरू, तगर, आंवला सुखा, चित्रक छाल, शातावर, कंकोल, खैरसार, जावित्री, सफेद चंदन प्रत्येक 4 ग्राम
कश्मीरी केसर 1 ग्राम

सबसे पहले देशी गाय के दूध को कड़ाही में डालकर अग्नि पर चढ़ाए और दूध आधा रहने पर उसमे नागौरी अश्वगंधा सोंठ पीपल और काली मिर्च का पाउडर और केशर डालकर गाढ़ा मावा तैयार कर ले और फिर गाय के घी में मावे को सुनहरी होने तक भून लें। इतनी प्रक्रिया के पश्चात भुना हुआ मावा एक प्लेट में निकालकर मिश्री या खांड की चाशनी एक तार की बना ले और मावे और अन्य बची हुई जड़ी बूटियों का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करके एक जान कर ले और फिर सूखे हुए से माल को ठंडा होने पर हाथ से रगड़कर छलनी में से निकाल ले और सुखा लें जिससे उत्तम क्वालिटी का दानेदार अश्वगंधा पाक तैयार हो जाएगा।

मात्रा लगभग दस दस ग्राम सुबह शाम गौदुग्ध के साथ प्रयोग करे और छोटे बच्चो के लिए मात्रा आधी कर दे।

अश्वगंधा पाक के लाभ आपकी संक्षेप में ऊपर बता दिए थे फिर भी कुछ समस्याओं में सिंगल या सहायक औषधी रूप में प्रयोग कर सकते है उनका एक लाइन में लाभ और बता देता हू।

वात संबंधी समस्याओं जैसे कमर दर्द, घुटनो के दर्द मांसपेशियों की कमज़ोरी बार बार नस पर नस चढ़ना आदि में अश्वगंधा पाक का प्रयोग बेहतरीन लाभ प्रदान करता है।

इसके अलावा मानसिक समस्या अवसाद तनाव से पीड़ित लोगो अनिद्रा की समस्या से पीड़ित लोगो या मानसिक श्रम करने वाले लोगो के लिए या जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है उनके लिए अश्वगंधा पाक उत्तम टॉनिक का कार्य करता है।

इसके अलावा जिन लोगो में धातु की कमज़ोरी हो वाजीकरण के तौर पर यह अच्छा लाभ देता हैं।

परसाईः साहित्य की वह कलम जो सत्ता से कभी नहीं डरी

हरिशंकर परसाई का नाम हिंदी साहित्य में एक ऐसी धारदार लेखनी के साथ उभरता है, जिसने हँसी के माध्यम से समाज की गहरी खामियों को उजागर किया। उनकी जयंती, २२ अगस्त, केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस साहित्यिक चेतना को याद करने का अवसर है, जिसने समाज के सामने सच का आईना रखा। परसाई केवल व्यंग्यकार नहीं थे; वे एक संवेदनशील कथाकार, गहरे विचारक और सामाजिक सुधारक भी थे। उनकी रचनाएँ, जैसे वैष्णव की फिसलन, तब की बात और थी, और निठल्ले की डायरी, न केवल पाठकों को हँसाती हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर सोचने के लिए मजबूर भी करती हैं। उनकी लेखनी का जादू यह था कि वह आम आदमी की भाषा में लिखी गई, जिससे गाँवों, कस्बों और शहरों के पाठक उनके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ सके।

परसाई का जन्म २२ अगस्त १९२४ को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमनी गाँव में हुआ। उनका बचपन अभावों और संघर्षों में बीता। पिता का देहांत जल्दी हो गया, और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इन कठिनाइयों ने परसाई को जीवन की कड़वी सच्चाइयों से कम उम्र में ही रूबरू करा दिया। यह अनुभव उनकी रचनाओं में साफ झलकता है। उनकी रचनाएँ, जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, सामाजिक असमानता, गरीबी और सत्ता के दुरुपयोग पर तीखा प्रहार करती हैं। परसाई की लेखनी में जो तीक्ष्णता और संवेदनशीलता दिखती है, वह उनके जीवन के इन कठिन अनुभवों की देन है। उनकी यह खासियत थी कि वे समाज की कमियों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करते थे, लेकिन उनकी हर पंक्ति में गहरी पीड़ा और सामाजिक चेतना छिपी होती थी।

परसाई का व्यंग्य केवल हँसाने का साधन नहीं था; वह एक सामाजिक हथियार था। वे कहते थे, व्यंग्य दुख से पैदा होता है। उनकी रचनाओं में यह दुख साफ दिखाई देता है, चाहे वह सत्ता की विसंगतियों पर उनकी तीखी टिप्पणी हो, धार्मिक पाखंड पर उनकी चोट हो, या मध्यवर्गीय जीवन की छोटी-मोटी विडंबनाओं का चित्रण हो। उदाहरण के लिए, उनकी रचना इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर में वे पुलिस और प्रशासन की भ्रष्ट कार्यप्रणाली का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस मजाक के पीछे एक गंभीर सवाल छिपा है—क्या हमारा सिस्टम वाकई इतना भ्रष्ट और लापरवाह है? परसाई का यह अंदाज उनकी रचनाओं को समयातीत बनाता है। आज भी, जब हम उनकी रचनाएँ पढ़ते हैं, तो वे उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। नेताओं की वादाखिलाफी, धर्म के नाम पर राजनीति, और भ्रष्टाचार पर उनके व्यंग्य आज के भारत पर भी सटीक बैठते हैं।

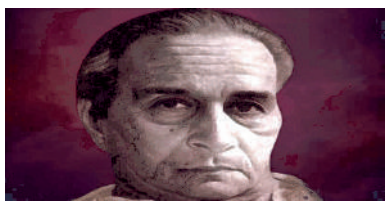

परसाई की एक और खासियत थी उनकी सादगी भरी भाषा। वे जटिल शब्दों या विद्वतापूर्ण लेखन से बचते थे। उनकी लेखनी में गाँव-देहात की मिट्टी की सोंधी खुशबू थी, जो आम पाठक को तुरंत अपनी ओर खींच लेती थी। उनकी रचनाएँ, जैसे पूछो परसाई से या शिकायत मुझे भी है, में आम आदमी की भाषा और उसके रोजमर्रा के जीवन की समस्याएँ साफ झलकती हैं। यही कारण है कि परसाई का पाठक वर्ग केवल साहित्यिक हलकों तक सीमित नहीं रहा। उनकी रचनाएँ छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों में भी उतनी ही लोकप्रिय थीं। उनकी यह क्षमता थी कि वे गंभीर मुद्दों को इतने सहज ढंग से पेश करते थे कि पाठक हँसते-हँसते समाज की सच्चाई से रुबरू हो जाता था।

कम लोग जानते हैं कि परसाई ने केवल व्यंग्य ही नहीं लिखा। उन्होंने कहानियाँ, निबंध और आलोचनात्मक लेखन भी किया। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण मिलता है। इसके अलावा, उन्होंने एक समय अध्यापन और पत्रकारिता भी की। कई अखबारों में उनके कॉलम बेहद लोकप्रिय थे। इन कॉलमों में वे तत्कालीन राजनीति, सामाजिक रुढ़ियों और प्रशासनिक खामियों पर तीखी टिप्पणियाँ करते थे। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि कई बार उन्हें राजनीतिक और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ा। लेकिन परसाई कभी नहीं डिगे। वे अपनी लेखनी के जरिए सत्ता, धर्मगुरुओं और समाज के तथाकथित ठेकेदारों को निशाने पर लेते रहे।

परसाई का लेखन न केवल पुरुष-प्रधान समाज की विसंगतियों को उजागर करता था, बल्कि उन्होंने स्त्रियों की स्थिति पर भी अपनी कलम चलाई। उनकी रचनाओं में पितृसत्ता, घरेलू जीवन की जटिलताओं और समाज में स्त्रियों के प्रति भेदभाव पर तीखी टिप्पणियाँ मिलती हैं। हालांकि, कुछ आलोचकों का मानना है कि उनकी रचनाओं में कभी-कभी पारंपरिक दृष्टिकोण भी झलकता है, लेकिन यह उनकी ईमानदारी को ही दर्शाता है। वे समाज की कमियों को, चाहे वह उनकी अपनी सोच में ही क्यों न हो, छिपाने की कोशिश नहीं करते थे। उनकी रचना भोलाराम का जीव में मध्यवर्गीय परिवार की छोटी-छोटी समस्याओं और पितृसत्तात्मक सोच का चित्रण इस बात का उदाहरण है।

परसाई की दूरदर्शिता उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को इतनी गहराई से समझा कि उनके व्यंग्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। परसाई का निजी जीवन भी उनकी लेखनी की तरह ही सादगी और संघर्ष से भरा था। वे आर्थिक तंगी से जूझते रहे, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे मजाक में कहा करते थे, लेखक को भूखा रहना चाहिए, तभी उसकी लेखनी में आग रहती है। यह केवल एक कथन नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का सच था। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में भी आर्थिक कठिनाइयाँ बनी रहीं, लेकिन लेखन के प्रति उनकी निष्ठा कभी कम नहीं हुई। उनकी यह प्रतिबद्धता उनकी रचनाओं में भी झलकती है, जो हमेशा निडर और बेबाक रही।

परसाई ने व्यंग्य को केवल मनोरंजन की विधा नहीं रहने दिया; उन्होंने इसे सामाजिक चेतना का हथियार बनाया। उन्होंने सिद्ध किया कि व्यंग्य केवल हँसी पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने और उसे बदलने के लिए भी हो सकता है। उनकी रचनाएँ हमें न केवल हँसाती हैं, बल्कि हमें अपने समाज, अपनी व्यवस्था और स्वयं अपने भीतर झाँकने के लिए मजबूर करती हैं। उनकी जयंती पर उन्हें याद करना केवल एक साहित्यकार को श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि उस चेतना को जीवित रखना है, जो हमें सच्चाई से रुबरू कराती है।

परसाई की लेखनी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने आसपास के पाखंड, भ्रष्टाचार और अन्याय को देखें और उसका विरोध करें। वे हमें सिखाते हैं कि हँसी के पीछे गंभीर चिंतन और नैतिक जिम्मेदारी होती है। उनकी जयंती पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी तरह निडर और ईमानदार बने रहेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हों। परसाई का साहित्य न केवल हिंदी साहित्य की धरोहर है, बल्कि यह एक ऐसी ज्योति है, जो हमें समाज की सच्चाई को देखने और उसे बदलने की प्रेरणा देती है। उनकी लेखनी की यह ताकत है कि वह हमें हँसते-हँसते सोचने पर मजबूर करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि समाज का दर्पण और उसकी आवाज है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

प्रेम पच्चीसा (भाग 7)

राजेंद्र रंजन गायकवाड़
सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रोहन ने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से उत्साह भरी आवाज़ आई, ₹रोहन जी, नमस्ते! आपको मुंबई में होने वाले भव्य कवि सम्मेलन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इस बार का आयोजन ख़ास है, क्योंकि इसमें न केवल प्रसिद्ध कवि, बल्कि फ़िल्मी सितारे और कई मशहूर गीतकार भी शामिल होंगे।₹ रोहन की आँखें चमक उठीं, लेकिन मन में एक हल्की सी घबराहट भी थी। इतने बड़े मंच पर अपनी कविताएँ प्रस्तुत करना, वो भी सितारों के बीच, कोई छोटी बात नहीं थी।

रोहन ने तुरंत अपनी डायरी में सम्मेलन का दिन समय और स्थान नोट किया। माया को हंसते बताया ,,मुंबई से बुलावा आया है। आप भी तैयार रहो राशि को भी घुमाकर लाते हैं। माया बोली ,,वाह बधाई हो मैने मुंबई नहीं देखा अभी तक,चलूंगी।

रोहन ने बताया कि इस बार का आयोजन खास है, माया जी, क्योंकि इसमें न केवल प्रसिद्ध कवि, बल्कि फिल्मी सितारे और कई मशहूर गीतकार भी शामिल होंगे।₹ माया की आँखें चमक उठीं, लेकिन मन में एक हल्की सी घबराहट भी थी। इतने बड़े मंच पर रोहन कविताएँ प्रस्तुत करना, वो भी सितारों के बीच, कोई छोटी बात नहीं थी।

रोहन, एक छोटे शहर का उभरता हुआ कवि, जिसकी कविताएँ सोशल मीडिया पर कुछ साल में वायरल हुई थीं, ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा मौका मिलेगा। उसने तुरंत हामी भर दी और सही समय से परिवार के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गया।

ट्रेन में सफर करते हुए, वह अपनी कविता की पंक्तियों को बार-बार दोहरा रहा था, ताकि मंच पर कोई गलती न हो।

मुंबई पहुँचते ही, आयोजकों ने उसका भव्य स्वागत किया। सम्मेलन का माहौल शानदार था चमचमाती रोशनी, मखमली पर्दे, और दर्शकों में बॉलीवुड के चमकते चेहरे। रोहन को बताया गया कि उसकी कविता के बाद, एक मशहूर गीतकार उसकी रचना पर आधारित गीत की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करेंगे। यह सुनकर रोहन का उत्साह दोगुना हो गया, पर घबराहट भी बढ़ गई।

कार्यक्रम शुरू हुआ। मंच पर एक के बाद एक नामी हस्तियाँ अपनी कला पेश कर रही थीं। रोहन की बारी आई। उसने गहरी साँस ली, माइक थामा, और अपनी कविता ₹सपनों का शहर₹ शुरू की। उसकी शब्दों की गहराई और आवाज़ का जादू दर्शकों को बाँध गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच, एक सुपरस्टार ने खड़े होकर उसकी तारीफ की। कविता ख़त्म होते ही, मशहूर गीतकार ने मंच संभाला और रोहन की कविता से प्रेरित एक गीत की पंक्तियाँ गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।

रात के अंत में, आयोजकों ने रोहन को बताया कि एक बड़े फिल्म निर्माता ने उसकी कविता सुनी और उसे अपनी अगली फ़िल्म के लिए गीत लिखने का प्रस्ताव देना चाहते हैं। रोहन के लिए यह सपना सच होने जैसा था। लेकिन, तभी उसे एक और कॉल आया एक रहस्यमयी आवाज ने कहा, "रोहन, तुम्हारी कविता में कुछ ऐसा है, जो हमें चाहिए। क्या तुम हमारे लिए एक खास प्रोजेक्ट पर काम करोगे?"

आगे कहानी यहाँ बढ़ती है। क्या रोहन इस नए प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या यह प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी बदल देगा, या कोई नई चुनौती लाएगा?

हरी इलायची चबाने के लाभ

डॉक्टर ने बताया कि 7 दिन तक सुबह खाली पेट 2 हरी इलायची चबाने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। हमारे किचन में मौजूद यह छोटी सी इलायची न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह हमारे शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होती है। आमतौर पर हरी इलायची का उपयोग खाने में किया जाता है, चाहे वह मीठा हो या किसी सब्जी का मसाला। लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी अत्यधिक हैं।

हरी इलायची चबाने के लाभः

पेट के दर्द और गैसः यह पेट में दर्द, गैस, जलन और खट्टी डकार जैसी समस्याओं में राहत दिलाती है।

कब्ज की समस्याः जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए हरी इलायची का सेवन बहुत लाभकारी होता है। सुबह खाली पेट चबाने से पेट साफ हो जाता है।

ल्यूकोरियाः महिलाओं के लिए यह समस्या भी कम हो सकती है। 2 इलायची चबाकर पानी पीने से राहत मिलती है।

नींद न आनाः यदि रात में सोने में कठिनाई हो रही हो, तो सोने से पहले इलायची का सेवन करने से नींद अच्छी आती है।

इम्यूनिटी बूस्टः हरी इलायची इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है।

मुंह के छालेः अगर मुंह में छाले हैं, तो इलायची को पीसकर छालों पर लगाने से आराम मिलता है।

हिचकीः हिचकी को बंद करने के लिए भी इलायची फायदेमंद होती है।

त्वचा और बालों के लिएः यह हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करती है।

जोड़ों का दर्द और वजन घटाने में मददः इलायची का सेवन जोड़ों के दर्द और वेट लॉस के लिए भी सहायक हो सकता है।

इसका सेवन बहुत आसान है। बस सुबह उठकर 2 इलायची लें, चबाएं और फिर पानी पी लें। इसके नियमित सेवन से आप इसके फायदों का अनुभव करेंगे।

रिश्तों का पराभव...!

पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव,
गृह कलेश के चलते रिश्तों का पराभव।
सहनशिलता 'शिखर' चढ़ी खतम वैभव,
इंसानियत सूली चढ़े ये कैसा हैं अनुभव।
आत्महत्या क्यों? करें पीढ़ी सोचे मानव,
बाहर क्यों खोजते हो घर में छिपे दानव।

पिता ने की पुत्री की शादी रहेगी आबाद,
खूब आएं खुशियां घर में बना रहे संवाद।
सोचते रहे छोटे-मोटे चल रहें वाद-विवाद,
आपसी रिश्तों में अभी डल रही है खाद।
सूरज पिता संग समोसे बेच देते है स्वाद,
ये परिवार हंसी-खुशी में सभी हैं अवाक!
(संदर्भ-पंखे में दुपट्टे का फंदा लगा की आत्महत्या)

संजय एम तराणेकर

व्यंग्य: मिस्टर माफी ठाकुर !

कस्तूरी दिनेश

हमारे संसदीय क्षेत्र में वे मि.माफी ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हैं। पुराने तपे-तपाये जनप्रतिनिधि हैं पर उनका मुंह क्या है कि बेलगाम घोड़ा! कब कहाँ सरपट भाग जाए दुलत्ती झाड दे, कोई ठिकाना नहीं! कभी किसी को आतंकवादी कह देंगे, कभी किसी को जिहादी! अपने विरोधियों को साम्प्रदायिक और फिरकापरस्त कह देना उनके बाएं हाथ का खेल है! भ्रष्टाचारी और कमीशनखोर शब्द तो उनके जिह्वा में खेलते रहते हैं। इन शब्दों का सुगन्धित, शीतल चन्दन वे कभी भी सामने वाले के माथे पर लेप सकते हैं! कभी-कभी तो बोलने की झोक में प्रतिक्रिया देते हुए वे अपनी ही पार्टी के कई नामी गिरामी ध्वज-वाहकों की इज्जत की मिट्टी पलीद कर देते हैं।

कल ही वे विरोध-पक्ष के एक जाने-माने जनप्रतिनिधि को डकैत कहने के मानहानि के अपराध में हाईकोर्ट से माफी मांगकर छूटे हैं! इधर छूटते ही आज उन्होंने विरोधी पार्टी के एक जनप्रतिनिधि का मुंह "गुंडा" शब्द के गुलाल से लाल कर दिया। अब तो उन्हें यह भी याद नहीं कि उन्होंने अपने उपमा-रूपक के सुगन्धित धूप-दीप से कितने बार विरोधियों का हवन-पूजन कर चुके हैं! मुझसे मुलाक़ात हुई और मैंने पत्रकार होने के कारण यह मामला उठाया तो वे हंसने लगे! उनकी हंसी में मंजा हुआ लोमड़पन था! मैं समझ गया वे उत्तर देना नहीं चाहते!

जनता के साथ उनकी पार्टी वाले भी उनके द्वारा विरोधियों को अलंकृत किये गये मजेदार प्यारे-प्यारे अलंकारों का खूब मजा लेते हैं। कई बार जब उनके द्वारा विभूषित सम्बोधनों का पानी सिर से उपर चला जाता है और थू-थू होने लगती है, तब पार्टी वाले यह कहकर पिंड छुड़ा लेते हैं कि यह उनकी निजी राय है, पार्टी का उससे कोई लेना-देना नहीं। एक तरह से कहें तो वे अब वे राजनीति के खुले सांड हो गये हैं। राजनीति के बाजार में वे कब कहाँ मुंह मार दें, कब किसको सींग मारकर उछाल दें उनका कोई ठिकाना नहीं!

राजनीति के ऐसे बहादुर, बेधड़क पार्टी-प्रवक्ता का आज अचानक अस्पताल के आई.सी.यू. में भर्ती होने होने के समाचार ने मुझे आश्चर्य के दसवें सागर में गोते लगाने को मजबूर कर दिया! शुभचिंतक होने के कारण उनकी मिजाजपुर्सी के लिए मुझे जाना ही था। मैं जब अस्पताल पहुंचा तब उन्हें आई.सी.यू. से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उनके सिर, हाथ, पैरों में जगह-जगह पट्टी बंधी हुई थी। मुझे देखते ही उनकी कंजी आँखों से अविरल अश्रु –प्रवाह होने लगा। मैं उनके माथे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देना चाहा परन्तु चोट के कारण उनके शरीर में सांत्वना के लिए कोई जगह ही नही बची थी!

काफी देर के बाद उन्होंने जज्ब करके अपने को थामा और सुबकते हुए कहने लगे—"अच्छा हो जाऊं फिर साले मल्लू पहलवान को छोड़ूंगा नहीं...! मैंने उसे बेपेंदी का लोटा क्या कह दिया, साले ने अपने आदमियों से मेरी यह हालत करवा दी। सोचा था कि गैंडे की औलाद ज्यादा से ज्यादा मेरे खिलाफ मानहानि का केस करेगा और मैं वहाँ माफ़ी-वाफी मांग कर छूट लूंगा पर इस आतंकी गुंडे ने तो मेरा हाथ-पाँव ही तुड़वा दिया दिनेश भाई...! वे फिर फफक पड़े! उनकी दयनीय दशा देखकर मेरी भी आँखें भर आईं। अब तक उनका हालचाल जानने के लिए उनकी पार्टी-कार्यकर्ताओं की भीड़ अंदर आने लगी थी। मैं चुपके से उठा और बाहर चला आया! मुझे उनके राजनीतिक जीवन में हिंसा से भरे ऐसे विस्फोटक मुकाम की आशा नहीं थी!

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के एक दिन बाद गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, बदल दिया पुलिस कमिश्नर

दिल्ली पुलिस में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री पर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने एसबीके सिंह को पुलिस आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया है। अब 1992 बैच के आइपीएस सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। गोलचा अप्रैल 2027 तक इस पद पर रहेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह नियुक्ति एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले और हमले में प्रथमदृष्टया पुलिस की चूक दिखाई देने के अगले ही दिन पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे एसबीके सिंह को पद से कार्यमुक्त कर दिया गया।

अब गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) काडर के 1992 बैच के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बना दिया है।

वह अब तक पुलिस महानिदेशक जेल के पद पर तैनात थे और पुलिस आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2027 तक रहेगा। इस बदलाव को सीएम पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि यह नियुक्त एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में हुई है, इसका मुख्यमंत्री पर हुए हमले की घटना से कोई लेना-देना नहीं है।

पूर्व पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का कार्यकाल विगत 31 जुलाई को खत्म होने पर गृह मंत्रालय ने उसी दिन अचानक दिल्ली होम गार्ड के डीजी 1988 बैच के यूटी काडर के आइपीएस एसबीके सिंह को पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया था।

पदभार संभलते ही उन्होंने स्थायी पुलिस आयुक्त के अंदाज में कामकाज भी शुरू कर दिया था, लेकिन महकमे में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि एसबीके सिंह आयुक्त पद पर बने रहेंगे या नहीं।

दिल्ली पुलिस के इतिहास में एसबीके सिंह सबसे कम समय मात्र 20 दिन ही पुलिस आयुक्त पद पर रह पाए। वह अब केवल होम गार्ड के डीजी पद की जिम्मेदारी संभालेंगे।

सतीश गोलचा बेहद सुलझे व अनुभवी आइपीएस माने जाते हैं। करीब छह साल बाद गृह मंत्रालय ने यूटी काडर के किसी आइपीएस को स्थायी चार्ज दिया है। इनसे पहले 2020 में दिल्ली दंगे के दौरान गृह मंत्रालय ने यूटी काडर के 1985 बैच के आइपीएस एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस आयुक्त का लुक आफ्टर चार्ज दिया था, लेकिन कुछ माह बाद उन्हें स्थायी चार्ज दे दिया गया था।

उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 1988 बैच के आइपीएस बालाजी श्रीवास्तव को आयुक्त का लुक आफ्टर चार्ज दिया गया था, लेकिन उन्हें 27 दिन बाद ही हटाकर गुजरात काडर के राकेश अस्थाना को स्थायी रूप से पुलिस आयुक्त बना दिया गया था।

एक साल बाद अस्थाना के सेवानिवृत्त होने पर तमिलनाडु काडर के संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया था। वह तीन साल आयुक्त पद पर रहे। चार साल तक गैर यूटी काडर के आइपीएस को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाने के बाद फिर से एसबीके सिंह को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी रहे

आइपीएस अधिकारी के रूप में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। 2022 से 2023 के बीच उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

जब उनकी दिल्ली पुलिस में वापसी हुई तब उन्हें विशेष पुलिस आयुक्त (इंटेलिजेंस) और फिर जेल महानिदेशक का पद दिया गया। अरुणाचल प्रदेश जाने से पहले उन्होंने विशेष आयुक्त (कानून व्यवस्था) जोन दो के रूप में कार्य किया और क्राइम ब्रांच का भी नेतृत्व किया।

वह दिल्ली के कई जिलों में डीसीपी और रेंज में संयुक्त आयुक्त भी रहे। कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों के लंबे अनुभव के कारण उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई।

No.14016/24/2007.UTS.I
भारत सरकार/Government of India
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
Kartavya Bhavan-3, New Delhi
Dated the 21st August, 2025

ORDER

With the approval of the Competent Authority, Sh. Satish Golcha, IPS (AGMUT:1992), presently posted as Director General (Prisons), Delhi, is hereby appointed to the post of the Commissioner of Police, Delhi with effect from the date of assumption of charge and until further orders.

(Anish Muraleedharan)
Director (S)
011-24010083

To

1. Sh. Satish Golcha, IPS (AGMUT:1992).
2. The Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
3. The Commissioner of Police, Delhi.
4. Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.

INTERNAL DISTRIBUTION

PS to HM/PS to MoS(N)/PS to MoS(BSK)/PSO to HS/Sr. PPS to Secretary (BM)/PSO to AS (UT)/PSO to JS(UT)/Personal file/Guard File/SO (IT)-to upload the order on MHA's website under AGMUT Cadre Management-order-transfer and posting.

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पक्ष या विपक्ष के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के उम्मीदवार हैं, हम उन्हें जिताने का पूरा प्रयास करेंगे- केजरीवाल

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से गुरुवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगा। इस दौरान उनके बीच देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर लंबी चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पक्ष या विपक्ष के उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के उम्मीदवार हैं। हम उन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने सभी दलों के सांसदों से अपील की कि देशहित में जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को जिताएं, ताकि देश को एक निष्पक्ष उपराष्ट्रपति मिल सके। साथ ही, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी पार्टियां भी दलगत राजनीतिक से हटकर देश और तेलगु गौरव के लिए वोट करेंगी।

गुरुवार को अपने आवास पर जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी ने विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन का समर्थन किया है। नामांकन के समय "आप" की तरफ से सांसद संजय सिंह वहां मौजूद थे। नामांकन के जस्टिस रेड्डी मुझसे मिले और हमने देश के मौजूदा हालात पर विस्तृत चर्चा की। जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, सैयद नसीर हुसैन और टीएमसी से कल्याण बनर्जी समेत कई अन्य नेता भी थे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर लंबी चर्चा की। इस चुनाव में गणित और रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विचार-विमर्श हुआ। हम सभी मिलकर जस्टिस रेड्डी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। यह चुनाव गुप्त मतदान (सीक्रेट बैलट) के जरिए होता है, जिसमें कोई दलगत अनुशासन (व्हिप) लागू नहीं होता। संसद में सामान्य प्रस्तावों या मतदान में व्हिप लागू होता है, लेकिन इस चुनाव में नहीं चलता है।

उन्होंने सभी दलों से अपील करते हुए कि जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें। उनका करियर एक जज के रूप में शानदार रहा है। उन्होंने देश और न्याय के हित में निडरता से कई बड़े फैसले दिए हैं। उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद पर बी. सुदर्शन रेड्डी जैसा व्यक्ति आएगा तो पद का मान-सम्मान और बढ़ेगा। जस्टिस रेड्डी पक्ष या विपक्ष के उम्मीदवार नहीं हैं, वे पूरे देश के उम्मीदवार हैं। इसलिए सभी दलों के सांसद देशहित में जस्टिस रेड्डी को वोट देकर जिताएं, ताकि देश को एक निष्पक्ष और सम्मानित उपराष्ट्रपति मिल सके। मैं जस्टिस रेड्डी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 9 सितंबर को मैं उन्हें जीत की बधाई भी दूंगा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों और तेलगू प्राइड का बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी राजनीति पार्टियां भी दलगत राजनीतिक से उपर उठाकर देश और तेलगु प्राइड के वोट करेंगे।

इस दौरान जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रतिनिधि संजय सिंह को बैठक में भेजा था, जिन्होंने मेरे उम्मीदवारी का समर्थन किया। मैं इसके लिए उनका आभारी हूं। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। उपराष्ट्रपति का कार्यालय कोई राजनीतिक नहीं है। यह एक उच्च संवैधानिक पद है, जिसे निष्पक्ष, स्वायत्त और स्वतंत्र होना चाहिए। ये गुण एक जज में होते हैं और इसीलिए मैंने विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल जैसे अनुभवी नेता के समर्थन से इस अनुरोध को स्वीकार किया। मैं यहां अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूं। यह समर्थन हमें देश में चल रहे हालात और भविष्य की चुनौतियों पर नए सिरे से सोचने को प्रेरित करता है। मैं एक साधारण नागरिक के रूप में, बिना किसी राजनीतिक दल से जुड़े, इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हूं। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सवाल पर कहा कि मैं आंध्र प्रदेश के नेताओं की ओर से नहीं बोल सकता, लेकिन मैं उनसे भी मिलकर समर्थन की अपील करूंगा।

सरकार की पीएम-कुसुम पहल के तहत स्थापित करेगा 1,884 सोलर वाटर पंप, 49 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

मुख्य संवाददाता

मुंबई भारत के पंप उद्योग में एक विश्वसनीय अग्रणी नाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हरित ऊर्जा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

कंपनी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) से "मागेल त्याला सौर कृषि पंप" योजना / पीएम-कुसुम बी योजना से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। इस अनुबंध में 1,884 ऑफ-ग्रिड डीसी सोलर फोटावोल्टाइक वाटर पंपिंग सिस्टम्स (एसपीडब्ल्यूपीएस) के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परिवहन, इंस्टॉलेशन, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य है। इस ऑर्डर का कुल मूल्य 49 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना किसानों को टिकाऊ, भरोसेमंद, ऊर्जा-कुशल और कम रखरखाव वाले सिंचाई समाधान उपलब्ध कराएगी।

क्रॉम्पटन की व्यापक सेवाओं के दायरे में पांच साल की वारंटी, मरम्मत और रखरखाव सेवाएँ तथा प्रत्येक इंस्टॉलेशन के लिए उन्नत रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) शामिल हैं, जो ग्रामीण एवं ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में दीर्घकालिक और भरोसेमंद कार्यक्षमता सुनिश्चित करेंगे।

कंपनी प्रशिक्षित कर्मियों, जिला-स्तरीय सेवा केंद्रों और द्विभाषी हेल्पलाइन के माध्यम से अनुबंध अवधि के दौरान त्वरित एवं विश्वसनीय सेवा समर्थन भी उपलब्ध कराएगी।

भारत एक ऐसा देश है, जहां की 60 फीसदी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, ऐसे में सिंचाई के लिए स्थायी और भरोसेमंद समाधान लगातार चुनौतीपूर्ण हैं।

पीएम-कुसुम और नेशनल सोलर मिशन जैसी सरकार द्वारा समर्थित योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी और अनियमित बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सोलर वाटर पंप को अपनाने में तेजी ला रही हैं। इसके साथ उन्नत तकनीक जैसे आईओटी-आधारित मॉनिटरिंग, कुशल सिंचाई की मांग, बढ़ती पर्यावरण जागरूकता इस बदलाव को और सशक्त बना रही है।

ऐसे अवसरों पर क्रॉम्पटन किसानों को उच्च-प्रदर्शन और भविष्य के लिए तैयार समाधान प्रदान करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है।

क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में होम इलेक्ट्रिकल्स एवं पंप्स के बिज़नेस हेड, रजत चोपड़ा ने कहा, "एमएसईडीसीएल द्वारा पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत 1,884 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स की आपूर्ति हेतु चुना जाना हमारे लिए गर्व का विषय है। 49 करोड़ रुपये के इस अनुबंध के माध्यम से हम किसानों को न सिर्फ कुशल और टिकाऊ, बल्कि दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मज़बूती देंगे। यह क्रॉम्पटन के उत्पाद की गुणवत्ता, सेवा नेटवर्क और तकनीकी विशेषज्ञता पर उपभोक्ताओं और संस्थाओं द्वारा जताए गए विश्वास का प्रतीक है। हम स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे और नवीनतम पंपिंग तकनीक के माध्यम से किसानों को सिंचाई हेतु जल की विश्वसनीय पहुँच प्राप्त करने में मदद करेंगे।"

85 से अधिक वर्षों की विरासत के साथ, क्रॉम्पटन ऊर्जा-कुशल, टिकाऊ और स्मार्ट पंपिंग तकनीकों के क्षेत्र में नवाचार करते हुए भारत के स्वच्छ ऊर्जा और जल सुलभता लक्ष्यों के अनुरूप अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रतीक:-'अग्नि-5 का सफल परीक्षण।'

20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया है। वास्तव में यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। कहना ग़लत नहीं होगा कि इस परीक्षण ने भारत की सामरिक क्षमता में वृद्धि और विश्वसनीय न्यूनतम निरोध (क्रेडिबल मिनिमम डेटेरेंस) बनाए रखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। पाठकों को बताता चलूं कि एमआईआरवी तकनीक (मल्टी अड्डे क्षमता) वाली अग्नि-5 मिसाइल कई ठिकानों पर हमला करने के साथ ही उसे पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एमआईआरवी क्षमता एक ही मिसाइल से एक से अधिक लक्ष्यों पर प्रभाव डालने की क्षमता है, जिससे दुश्मन की विरोधी रणनीतियों का मुकाबला कारगर ढंग से किया जा सकता है। यह मिसाइल आईसीबीएम / इंटर-मीडियाट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की है, जिसकी रेंज 5,000–8,000 किमी तक; हालिया वेरिएंट लगभग 7,000 किमी क्षमता के साथ भी रिपोर्ट की गई है।सरल शब्दों में कहें तो इस मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक है तथा इसे 8,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका को छोड़कर पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को निशाना बनाया जा सकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की भारत के इस मिसाइल परीक्षण ने नींद उड़ाई दी है।पश्चिमी देशों की रणनीतिक नज़र भी इस पर है, क्योंकि भारत के पास अब अपनी आईसीबीएम क्षमता है।इसकी प्रणाली की यदि हम यहां पर बात करें तो इसमें तीन-स्तरीय ठोस ईंधन, सड़क-मोबाइल, कैनिस्टर आधारित लॉन्चर मौजूद है तथा वारहेड क्षमता लगभग 1,500–1,650 किलोग्राम है।सरल शब्दों में कहें तो रोड-मोबाइल लॉन्चर से

इसका (अग्नि-5) का प्रक्षेपण आसानी से हो सकता है तथा यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। पाठकों को बताता चलूं कि परीक्षण के दौरान समुद्र में तैनात जहाजों, राडारों ने मिसाइल की उड़ान का वास्तविक समय में आकलन किया है।एमआईआरवी तकनीक समर्थित एक मिसाइल से कई स्वतंत्र लक्ष्य निशान किए जा सकते हैं।इसकी गति या स्पीड लगभग मैक 24 (₹29,400 किमी/घंटा) है, यानी कि आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा। इसमें आरएलजी-आइएनएस यानी कि रिंग लेजर जिनरोस्कोप–इर्शियल नेविगेशन सिस्टम तथा मल्टी जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम लगा है। अग्नि-5 मिसाइल के वज़न और आकार की यदि हम यहां पर बात करें तो अग्नि-5 मिसाइल की लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है तथा इसका वजन करीब 50 टन है। कहना ग़लत नहीं होगा कि इस मिसाइल के परीक्षण के साथ ही भारत अब उनसे देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास एमआईआरवी-युक्त आईसीबीएम है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस आदि। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अग्नि-5 के परीक्षण से भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है, जिनके पास आईसीबीएम क्षमता है। आईसीबीएम का मतलब है अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल)। पाठकों को बताता चलूं कि इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल भारत की रक्षा अनुसंधान ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पाठकों को बताता चलूं कि इस मिसाइल (अग्नि-5) के सफल परीक्षण के साथ ही अब भारत की जद में पाक-चीन के साथ आधी दुनिया आ गई है और भारत की यह सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह मिसाइल अधिकतम 600 किमी. की ऊंचाई पर जा सकती है। अंत में यही कहूंगा कि अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण ने न सिर्फ़ भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊँचाई दी है, बल्कि कई देशों की नींद उड़ा दी है। वास्तव में यह हमारे देश की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) और 'सस्ता, टिकाऊ, शक्तिशाली' उत्पाद —'दाम कम, दम ज्यादा' — के सिद्धांत पर जोर देते आए हैं, जिससे 'मेक इन इंडिया' को और मजबूती मिले।अग्नि-5 का परीक्षण इसी दिशा में भारत का एक बड़ा, सफल व सशक्त व विकसित भारत का प्रयास है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार,

राजा इकबाल सिंह डमी मेयर हैं, उनमें अपने ही पार्षद की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जांच कराने की हिम्मत नहीं है- अंकुश नारंग

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में उस समय हंगामा मच गया जब डिप्टी कमिश्नर ने भाजपा पार्षद को ब्लैकमेलर कहा। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि राजा इकबाल सिंह डमी मेयर हैं। इसीलिए वह अपने ही पार्षद की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जांच कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भाजपा पार्षद ने डिप्टी कमिश्नर पर जेई के जरिए पैसे लेने का आरोप लगाया, लेकिन मेयर ने अधिकारी का समर्थन किया। स्थायी समिति में डिप्टी कमिश्नर ने भाजपा पार्षद को ब्लैकमेलर भी कहा, लेकिन भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया। मेयर को बताना चाहिए कि उनकी डिप्टी कमिश्नर से क्या मिलीभगत है, जो उन्हें बचाना चाहते हैं?

एमसीडी में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने कहा कि गुरुवार को सदन के अंदर शुरुआत में डीडीए के दो सदस्यों की घोषणा की गई। कृष्णा देवी राघव और सीएस पवार को डीडीए का सदस्य बनाया गया। इसके बाद मैं स्थायी समिति के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मेयर ने मुझे बोलने नहीं दिया। क्योंकि मेयर और अधिकारियों की मिलीभगत है। स्थायी समिति के अंदर एक अधिकारी ने भाजपा पार्षद को ब्लैकमेलर कहा। अधिकारी ने उन्हें ब्लैकमेलर क्यों कहा? क्योंकि भाजपा पार्षद ने आवाज उठाई थी कि

उनके इलाके में जेई पैसे मांग रहा है। जब भाजपा पार्षद ने जेई से पूछा, तो जेई ने कहा कि डीसी पैसे मांग रहे हैं। जिसके बाद भाजपा पार्षद ने यह बात कमिश्नर को बताई।

अंकुश नारंग ने कहा कि एमसीडी कमिश्नर को इस मामले की तुरंत जाँच के आदेश देने चाहिए। लेकिन जाँच बिठाने की बजाय, कमिश्नर ने डीसी बादल कुमार का समर्थन किया और सभी पार्षदों को ब्लैकमेलर बताया। जो मुद्दा भाजपा को उठाना चाहिए था, उसे आज आम आदमी पार्टी ने सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि डीसी बादल कुमार का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो रहा था। उन्हें एक साल का एक्सटेंशन मिला था, जो 2024 में समाप्त हो रहा था। 19 दिसंबर 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बादल कुमार अब डीसी के रूप में काम नहीं करेंगे। इसे पूरे सदन ने पारित कर दिया। लेकिन आज भी वह डीसी बने हुए हैं।

उन्होंने कहा कि बादल कुमार ने स्थायी समिति में खड़े होकर एक पार्षद के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें ब्लैकमेलर कहा। भाजपा को यह मुद्दा उठाना चाहिए था। जब भाजपा कहती है कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, अफसर राज खत्म करेंगे, तो आज मेयर की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अफसरों का साथ दिया, अपने ही पार्षद को दरकिनार किया और सदन स्थगित कर दिया।

अंकुश नारंग ने कहा कि मैं शोर नहीं मचा रहा था, बस अपनी बात रख रहा था। मैं एक प्रस्ताव भी लाया था जिसमें कहा गया था कि बादल कुमार को तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए और उन्हें आगे डीसी के तौर पर काम न करने दिया जाए। लेकिन उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया।

राधाष्टमी के अवसर पर साहित्यकार सम्मान समारोह व कवि सम्मेलन 31 अगस्त को

प्राग हरि साहित्यिक और आध्यात्मिक शोध संस्थान, जयपुर एवं ब्रजवानी जन सेवा समिति, ब्रज नगर, डीग (राजस्थान) के संयुक्त तत्वावधान में होगा वृहद आयोजन

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

मथुरा। ट्रांसपोर्ट नगर/मंडी समिति के पीछे मंशा टीला स्थित पं लटूर प्रधान फार्म हाउस में प्राग हरि साहित्यिक व आध्यात्मिक शोध संस्थान, जयपुर एवं ब्रजवानी जन सेवा समिति, ब्रज नगर (डीग) राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राधाष्टमी के पावन अवसर पर साहित्यकार एवं पत्रकार सम्मान समारोह 31 अगस्त 2025 को प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा।

जानकारी देते हुए ब्रजवानी जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र शर्मा ₹हरि₹ ने बताया है कि कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्वाह्न 11 बजे सरस्वती वंदना के साथ होगा।साथ ही ₹रम गयौ मन वृंदावन मेंर ब्रजभाषा गीत संग्रह का विमोचन किया जाएगा।तत्पश्चात 11:30 बजे से सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके अलावा 12 बजे से 02:30 बजे तक कवि सम्मेलन का आयोजन होगा।जिसमें देश भर के कई प्रख्यात कवियों द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा।

प्राग हरि साहित्यिक और आध्यात्मिक शोध संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सरोज गुप्ता (जयपुर) ने बताया है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ओम प्रकाश पांडेय ₹निर्भय₹ करेंगें।साथ ही मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रज भूषण चतुर्वेदी एवं विशिष्ट अतिथि प्रख्यात साहित्यकार/ पत्रकार डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी व कन्हैया लाल सारस्वत होंगे।कार्यक्रम के संयोजक/संचालक प्रख्यात कवि अभिषेक ₹अमर₹ (ब्रज नगर, डीग) हैं।

संत घनश्याम दास ठाकुरजी महाराज का 90 वां त्रिदिवसीय जन्म महोत्सव धूमधाम से सम्पन्न

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। मदनमोहन घेरा स्थित श्रीराधा केलि कुंज (निकट श्री सनातन गोस्वामी समाधि मंदिर) में चल रहा पूज्य संत घनश्याम दास ठाकुरजी महाराज का 90 वां त्रिदिवसीय जन्म महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ।उत्सव में ठाकुरजी द्वारा रचित पदों का संगीत की मृदुल स्वर लहरियों के मध्य गायन किया गया।

इस अवसर पर पूज्य संत घनश्याम दास ठाकुरजी महाराज के चित्रपट का संतों एवं भक्तों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजन-अर्चन किया गया।तत्पश्चात वृहद संत-विद्वत सम्मेलन आयोजित हुआ।जिसमें अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रीगोरीलाल कुंज के श्रीमहंत स्वामी किशोर दास देवजू महाराज ने कहा कि पूज्य घनश्याम दास ठाकुरजी महाराज बालपन से ही ठाकुरश्री रासबिहारी सरकार की सेवा में संलग्न रहे, बाद में संत बालकृष्ण दास महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और वे श्रीधाम वृन्दावन में ही भगवद भक्ति में लीन हो गए।

रासाचार्य स्वामी कुंजबिहारी शर्मा ने कहा कि पूज्य घनश्याम दास ठाकुरजी महाराज श्रीधाम वृन्दावन की बहुमूल्य निधि थे।सांसारिक व भौतिक जीवन से उन्हें कोई मोह नहीं था। संत सेवा व गुरु भक्ति ही उनके जीवन के अभिन्न अंग थे।

ब्रज साहित्य सेवा मण्डल के अध्यक्ष डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि पूज्य घनश्याम दास ठाकुरजी महाराज ब्रज के प्रख्यात संत बालकृष्ण दास महाराज के अत्यन्त प्रिय व ठाकुरश्री रासबिहारी सरकार के अनन्य उपासक थे।

महन्त किशोरी शरण भक्तमाली (मुखियाजी) ने कहा कि सन्त घनश्याम दास ठाकुरजी गीता वाटिका (गोरखपुर) के प्रख्यात संत राधा बाबा एवं प्रकांड विद्वान हनुमान प्रसाद पोद्दार (भाईजी) के भी विशेष कृपा पात्र थे।उनके द्वारा सैकड़ों पदों की रचना की गई।पूर्व में उनका स्मृति ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है।

महोत्सव में भागवताचार्य डॉ. हरेकृष्ण शरद, बाबा कुंजबिहारी शरण महाराज, महन्त ब्रजबिहारी दास महाराज, महंत सोहनी शरण महाराज, सन्त विद्याधर दास, सन्त बिहारी दास महारा, डॉ. चंद्रेश गुप्ता, पूर्व प्राचार्य शिवकुमार गोयल, विपुल बिहारी शर्मा, इंजीनियर ब्रजेश मिश्रा, आचार्य रामनिवास शुक्ला, रासाचार्य स्वामी जयप्रिया शरण महाराज, युवा साहित्यकार डॉ. राधाकांत शर्मा, गौरव शर्मा आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।संचालन प्रमुख शिक्षाविद् डॉ. चंद्र प्रकाश शर्मा ने किया।इससे साथ ही नित्य रास रस चर्चा, निकुंज रासलीला दर्शन एवं संत, ब्रजवासी, वैष्णव सेवा (वृहद भंडारा) आदि के आयोजन भी सम्पन्न हुए।

बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा: सुशांत शुक्ला

पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन ने 17 बच्चियों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया
पायल लाठ ने बच्चों को दिया नया संबल

सुनील चिंचोलकर

बिलासपुर,छत्तीसगढ़। शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हुए पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन ने एक सराहनीय पहल की है। फाउंडेशन ने मोहन्ती गर्ल्स स्कूल में एक प्रेरणादायक व भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूल की 17 बच्चियों की शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेने की घोषणा की।

कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला मुख्य अतिथि, विजय अग्रवाल व सुशील अग्रवाल विशिष्ट अतिथि और आशा अग्रवाल और पूनम श्रीवास्तव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुशांत शुक्ला के हाथों बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी किताबें भेंट की गईं। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापिका पायल लाठ ने कहा कि गोद ली बच्चियों की क़िताबें, फीस और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताएँ फाउंडेशन द्वारा पूरी की जाएंगी। इस मौके पर विधायक शुक्ला ने कहा कि मै हर बच्चे की शिक्षा में सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। फाउंडेशन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए श्रीराम फाउंडेशन, विशाल बजाज, लोकेश ठक्कर एवं राहुल अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में प्राचार्य अंजना लाल, प्राची बरगाह,अनिल जेम्स, एन्न लदेर, एच मसीह, एएफ हाश्मी,एस कटारे, एमके वर्मा, पायल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह राजपूत, सचिव चंचल सलूजा एवं अप्पू केशरी विशेष रूप से उपस्थित थे।

संस्था द्वारा बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने से लेकर उनकी फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और पढ़ाई से जुड़ी हर जरूरत पूरी की जाएगी। फाउंडेशन की अध्यक्ष पायल लाठ ने कहा कि "शिक्षा ही ऐसा साधन है जो किसी भी बच्चे का भविष्य बदल सकता है। हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई से वंचित न हो।"

वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने देशभर के व्यापारियों से किया स्वदेशी अपनाने का आह्वान

स्वदेशी उत्पादों का प्रोत्साहन राष्ट्र निर्माण की आधारशिला – वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान
सभी व्यापारी अधिक से अधिक भारत में निर्मित वस्तुएं बेचें और जनता को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित करें – वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान
जब देश की 140 करोड़ जनता विदेशी उत्पादों को त्यागकर भारतीय वस्तुओं को अपनाएगी, तभी भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा।₹ – वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

आगरा, संजय सागर सिंह। वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए देशभर के व्यापारियों से अपील की है कि सभी व्यापारी अधिक से अधिक भारत में निर्मित वस्तुएं बेचें और जनता को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि ₹स्वदेश भारत की आत्मा है₹ और यह आत्मा तभी जागृत होगी जब हर नागरिक देशी वस्तुओं को प्राथमिकता देगा।

वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने यह विचार आगामी स्वदेश जन जागरण अभियान के संदर्भ में व्यक्त किए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इस अभियान की पूर्व संध्या पर 23 अगस्त को दिल्ली में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई प्रमुख नेता देश भर से आमंत्रित व्यापारियों को संबोधित करेंगे।

इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों और आमजन को देश में निर्मित वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। श्री खान साहब ने कहा, ₹आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, आज प्रधानमंत्री मोदी उसे एक नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, ₹जब देश की 140 करोड़ जनता विदेशी उत्पादों को त्यागकर भारतीय वस्त्र, जूते, घड़ियां, मोबाइल, लैपटॉप जैसी वस्तुओं को अपनाएगी, तभी भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा।"

वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने सरकार की व्यापारी हितैषी नीतियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जीएसटी के सरलीकरण, 18% और 5% स्लैब जैसे प्रस्तावों से व्यापारी वर्ग में उत्साह है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय व्यापारी वर्ग असुरक्षा के माहौल में व्यापार करता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है।

उन्होंने कहा, ₹आज माफिया और अपराधी या तो जेल में हैं या पलायन कर चुके हैं। भाजपा सरकार ने भयमुक्त शासन दिया है जो 'रामराज्य' की अवधारणा के निकट है।"

वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने यह भी बताया कि भाजपा सरकार ने व्यापारियों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना, नई एक्सप्रेसवे परियोजनाएं, रेल और हवाई सेवाओं के विस्तार, तथा उन्नत आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

तनाव से हैं परेशान तो आयुर्वेद से करें उपचार... पांच मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी 'आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट ओपीडी

दिल्ली सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पांच मेडिकल कॉलेजों में आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट ओपीडी शुरू की जाएगी जहाँ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से तनाव का प्रबंधन किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस योजना को पूरे दिल्ली में विस्तारित किया जाएगा जिससे नागरिकों को समग्र स्वास्थ्य समाधान मिल सकेगा।

नईदिल्ली। आधुनिक जीवनशैली में तनाव बढ़ने के साथ ही लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा रहा है। वर्ष 2015-16 में किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भारत में 10.6 वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित मिले थे।

वहीं राष्ट्रीय अध्ययनों के मुताबिक वर्तमान में देश की 15 प्रतिशत वयस्क आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। मानसिक विकार वाले 70 से 92 प्रतिशत लोगों को उचित उपचार नहीं मिल पाता हैं।

इस खाई को भरने की पहल दिल्ली में भी की जा रही है। इसके तहत पांच मेडिकल कॉलेजों में आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट ओपीडी शुरू होगी। इसके जरिए मानसिक तनाव से संबंधित समस्या की शीघ्र पहचान, समय रहते उपचार और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आयुष उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, डॉ. बीआर सूर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के साथ ही इहबास अस्पताल में ओपीडी सेवा की शुरुआत होगी।

आयुर्वेदिक औषधियां, होम्योपैथिक दवा, पंचकर्म, योग-ध्यान, प्राणायाम के साथ ही जीवनशैली परामर्श से चिंता, थकान, अनिद्रा और मानसिक तनाव आदि का उपचार किया जाएगा।

प्रत्येक मंगलवार और बृहस्पतिवार को नियमित ओपीडी के समय पर मरीज इसका लाभ उठा सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद सभी 11 जनपदों में इसका विस्तार भी किया जाएगा।

आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट ओपीडी के माध्यम से दिल्ली के प्रत्येक नागरिकों को भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को जोड़ते हुए एक समग्र, प्रभावी और सुलभ समाधान उपलब्ध करा रहे हैं। यह पहल न केवल सरकारी अस्पतालों पर मरीजों के बोझ को कम करेगी, बल्कि लोगों के अधिक स्वस्थ, संतुलित और तनाव-मुक्त जीवन जीने में भी सक्षम बनाएगी।

- डॉ. पंकज सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-दिल्ली

आबादी के मुताबिक एक से भी कम मनोचिकित्सक

भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ प्रति 10 हजार की आबादी पर 2443 विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) है। वहीं प्रति एक लाख की जनसंख्या पर आयु-समायोजित आत्महत्या दर 21.1 प्रतिशत है।

इंडियन जर्नल आफ साइकाइट्री के अनुसार भारत में प्रति एक लाख लोगों पर 0.75 मनोचिकित्सक हैं , जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति एक लाख की आबादी पर कम से कम 3 मनोचिकित्सकों की सिफारिश करता है।

खराब मानसिक स्वास्थ्य से नुकसान

कार्यस्थल पर प्रदर्शन व कार्यकुशलता का कम होना।

पारस्परिक संबंधों, आत्मविश्वास और सामाजिक संबंधों का प्रभावित होना।

दैनिक जीवन में सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके होते हैं प्रभावित।

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: युवाओं की सुरक्षा और समाज की ज़िम्मेदारी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

भारत एक युवा देश है।यहाँ की आधी से अधिकआबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और इस युवा शक्ति को ही ₹नवभारत का भविष्य₹ कहा जाता है। परंतु यही युवा आज एक ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं जो मनोरंजन के नाम पर धीरे-धीरे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अंधकार की ओर धकेल रहा है। यह जाल है ऑनलाइन गेमिंग का अनियंत्रित विस्तार। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुलभता ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विशाल बना दिया है। आज स्थिति यह है कि लगभग 50 करोड़ भारतीय युवा किसी-न-किसी रूप में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं। इनमें से लाखों युवा इसकी लत के शिकार हो चुके हैं।इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने "प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025" संसद में प्रस्तुत किया जो पास हो गया।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि पिछले दस वर्षों में भारत में इंटरनेट उपयोग कर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। सस्ते स्मार्टफोन और डेटा पैक की वजह से आज गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। इस इंटरनेट क्रांति का एक सबसे बड़ा प्रभाव ऑनलाइन गेमिंग के रूप में सामने आया। पीयूबीजी, फ्री फायर,बीज़ीएमआई, कॉल ऑफ़ ड्यूटी और विभिन्न फैंटास्टि स्पोर्ट्स जैसे गेम युवाओं में इस कदर लोकप्रिय हो गए कि वे पढ़ाई, खेल-कूद और सामाजिक जीवन से दूर होकर वर्चुअल दुनियाँ में खोते चले गए।20 अगस्त 2025 को देर शाम केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने संसद भवन के बाहर कहा कि यह कानून इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ने करोड़ों युवाओं को अंधकार में डाल दिया है और समाज से बड़े पैमाने पर फीडबैक प्राप्त हुआ कि अब इसे नियंत्रित करना ही पड़ेगा, आज के युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। ऑनलाइन गेमिंग के तीन सेगमेंट्स हैं:पहला- ई-स्पोर्ट्स, दूसरा- ऑनलाइन सोशल गेमिंग और तीसरा- ऑनलाइन मनी गेमिंग।इस बिल के माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट किया जाएगा और इसको सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। हमारे द्वारा एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए सही नहीं है। कुछ गेम्स ऐसे हैं, जिनमें परिवार की जिंदगीभर की बचत ऑनलाइन गेम में चली जाती है।

साथियों बात अगर हम डब्लूएचओ द्वारा गेमिंग डिसऑर्डर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या व भारत सरकार ने इस समस्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा मानते हुए हस्तक्षेप करने की करें तो,विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में ही गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य की श्रेणी में शामिल किया था। डब्लूएचओ का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऑनलाइन गेम में इतना डूब जाए कि उसके पढ़ाई-लिखाई,रोजगार नींद, खान-पान, सामाजिक संबंध और पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़े, तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है।भारत में भी कई राज्यों में ऐसी घटनाएँ सामने आईं जहाँ बच्चे और किशोर ऑनलाइन गेम हारने के बाद तनाव, डिप्रेशन और यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर बैठे। माता-पिता ने शिकायत की कि उनके बच्चे मोबाइल स्क्रीन से अलग नहीं हो पा रहे, नींद पूरी नहीं हो रही, आँखों की रोशनी प्रभावित हो रही है, और पैसे खर्च करने की आदत भी नियंत्रण से बाहर जा रही है।इन्हीं कारणों से भारत सरकार ने इस समस्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा मानते हुए हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया।

साथियों बात अगर हम,इस कानून को जरूरी बनाने वह बिल की मुख्य बातों की करें तो, (1) युवा पीढ़ी पर खतरा-लगभग 50 करोड़ युवा ऑनलाइन गेम्स की लत में हैं। यह संख्या भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है।(2) आर्थिक शोषण-इन-ऐप परचेज़ और कैश रिवार्ड्स ने युवाओं को आर्थिक रूप से शोषित किया। कई परिवार कर्ज़ में डूबे। (3) अपराध की घटनाएँ- कई राज्यों में देखा गया कि बच्चे चोरी या अपराध की राह पर चल पड़े ताकि वे गेमिंग के लिए पैसे जुटा सकें। (4) स्वास्थ्य संकट-मानसिक तनाव, डिप्रेशन, आँखों और शरीर से संबंधित रोगों का प्रसार। (5)समाजिक असंतुलन-युवाओं का वास्तविक जीवन से कटना और वर्चुअल दुनिया में गुम होना। (6) फीडबैक का दबाव-समाज से व्यापक स्तर पर सुझाव मिले कि सरकार को इस पर नियंत्रण करना ही होगा।प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की मुख्य बातें (1) गेम्स की कैटेगरी तय होगी-कौन सा गेम "स्किल-बेस्ड"है और कौन सा "चांस-बेस्ड",यह सरकारनिर्धारित करेगी। (2)लाइसेंस प्रणाली- बिना सरकारी अनुमति के कोई भी कंपनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म नहीं चला सकेगी। (3)आयु सीमा-नाबालिगों (18 साल से कम) के लिए कई तरह की रोक लगाई जाएगी। (4) समय

सीमा-गेम खेलने की अधिकतम समय सीमा तय होगी ताकि युवा पूरी रात ऑनलाइन गेम न खेलें। (5) वित्तीय नियंत्रण-ऑनलाइन गेम्स में निवेश और इन-ऐप परचेज़ पर कड़ा नियमन।

साथियों बात अगर हम सरकार के साथ संदेश की करें तोसरकार ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करना चाहती, बल्कि उसे विनियमित (रेगुलेट) करना चाहती है ताकि यह उद्योग भी चले और युवाओं की सेहत भी सुरक्षित रहे।समाज की ज़िम्मेदारी और नागरिकों की भूमिका,कानून अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज और परिवार भी जागरूक हों। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें, शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाएँ, और युवाओं को भी समझना चाहिए कि जीवन केवल वर्चुअल गेम्स तक सीमित नहीं है।प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025" भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल युवाओं को अंधेरे से बाहर निकालने का प्रयास है बल्कि यह संदेश भी है कि भारत सरकार नागरिकों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है।इस कानून से यह स्पष्ट है कि भारत केवल डिजिटल शक्ति बनने की दिशा में ही नहीं, बल्कि जिम्मेदार डिजिटल समाज बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

साथियों बात अगर हम ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने की करें तो, हमारे देश में कैसीनो पर तो बैन हैं, लेकिन मोबाइल फोन में करोड़ों कैसीनोस चल रहे हैं और अब उसपर एक बिल पास करवाकर पाबंदी लगाई जाएगी। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित किया जाएगा और कोई भी ऑनलाइन गेम्स,जिसमें लोग पैसा लगाते हैं और जीतने पर पैसे कमाते हैं, उनपर रोक लग जाएगी। ऐसे गेम्स को ऑनलाइन मनी गेम्स कहते हैं। इस बिल में 4 बड़ी बातें हैं। पहली बात, ऑनलाइन मनी गेम्स की सर्विस देना, उसे चलाना और यहां तक कि प्रचार करना भी गैरकानूनी होगा। दूसरा अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं मिल सकती हैं। तीसरा,ऐसे गेम्स खेलनेवालों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। सज़ा या जुर्माना ऐसे गेम्स की सर्विस देने वालों,इनका विज्ञापन करने वालों या आर्थिक मदद देने वालों को होगी।और चौथा,गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने केलिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। जो ये तय करेगी कि ऑनलाइन मनी गेम्स कौन से हैं। और बिना पैसे वाले गेम्स यानें इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।जिसमें खिलाड़ी अकेले या फिर टीम के रूप में एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। इस बिल के दायरे में स्किल बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम्स दोनों हैं। स्किल बेस्ड गेम्स जैसे शतरंज और रम्मी में लोगों के स्किल्स यानी कौशल और रणनीति पर उस गेम का नतीजा निर्भर करता है। और चांस बेस्ड गेम्स जैसे लॉटरी में नतीजा किस्मत या संयोग पर निर्भर करता है।इसमें खेलने वालों के कौशल का असर बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। और कई देशों में इसे गंभीलिंग यानी जुआ माना जाता है। आईटी मंत्री ने कहा है कि सरकार गेमिंग इंडस्ट्री की मदद करना चाहती है। लेकिन जब उद्योग के मुनाफे और समाज के हितों में टकराव हो, तो मोदी सरकार हमेशा समाज का पक्ष लेगी।आपने बड़े-बड़े फिल्मस्टार्स और खिलाड़ियों को ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन करते देखा होगा। क्रिकेट और बाकी खेलों के कई ऐसे मोबाइल अप्प्स हैं, जिसमें पैसे लगाकर टीम बनानी होती है। और विज्ञापनों में ऐसा दिखाया जाता है कि सिर्फ 50 या 60 रुपए लगाकर आपकरोड़ों रुपए जीत सकते हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: युवाओं की सुरक्षा और समाज की ज़िम्मेदारी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदमऑनलाइन मनी गेम की सर्विस देना, संचालन करना, प्रचार करना गैरकानूनी होगा-सरकार का चलेगा चाबुक-3 साल की सजा,एक करोड़ जुर्मानाकानून अपनी जगह ज़रूरी है,लेकिन समाज,परिवार माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें, शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाएँ।

हीरो एक्सट्रीम 125आर का सिंगल सीट वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में Hero Xtreme 125R का सिंगल सीट वेरिएंट लॉन्च किया है। यह वेरिएंट स्प्लिट-सीट ABS वेरिएंट से 2000 रुपये सस्ता है। Hero Xtreme 125R सिंगल सीट वेरिएंट में सिंगल-सीट को राइडर और पीलियन को ध्यान में रखकर लाया गया है। इसमें ऑल-LED सेटअप और सिंगल चैनल ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसका इंजन 11.4bhp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प हाल ही में भारतीय बाजार में नई Glamour X को लॉन्च किया है। यह भारत की पहली सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल वाली बन गई है। अब कंपनी ने Hero Xtreme 125R को सिंगल सीट के साथ लॉन्च किया है। इसे सिंगल सीट देने के साथ ही और भी कई बेहतरीन फीतर्स से साथ लाया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Hero Xtreme 125R single seat को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है।

कितनी है कीमत?

Hero Xtreme 125R सिंगल सीट वेरिएंट को चुपचाप लॉन्च किया गया है। यह नया सिंगल-सीट वेरिएंट टॉप-स्पेक स्प्लिट-सीट ABS वेरिएंट से 2,000 रुपये सस्ता है। इस वेरिएंट को स्प्लिट-सीट IBS और स्प्लिट-सीट ABS वेरिएंट के बीच में रखा गया है। स्प्लिट-सीट IBS वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 98,425 रुपये है, जबकि स्प्लिट-सीट ABS वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1.02 लाख रुपये है। एक्सट्रीम 125R सिंगल सीट वेरिएंट को 1 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है।

क्या हैं बदलाव?

Hero Xtreme 125R सिंगल सीट वेरिएंट में ज्यादा बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें सिंगल-सीट को राइडर और पीलियन को ध्यान में रखकर लेकर आया गया है। हालांकि, यह स्प्लिट-सीट वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा कम स्पोर्टी दिख सकता है। यह ऑल-LED सेटअप, स्पोर्टी मफलर कवर, 276mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक, हजार्ड लैंप, सिंगल चैनल ABS जैसे फीचर्स के साथ आती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

Hero Xtreme 125R सिंगल सीट वेरिएंट में 124.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसका इंजन 11.4bhp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

इनसे होता है मुकाबला

भारतीय बाजार में Hero Xtreme 125R का मुकाबला, TVS Raider 125, Honda CB 125 Hornet और Bajaj Pulsar N125 जैसी मोटरसाइकिल से देखने के लिए मिलता है।

टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी कमर्शियल कार्गो स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें क्या है खासियत और कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी कमर्शियल वाहनों की भारतीय बाजार में काफी ज्यादा मांग रहती है। इस सेगमेंट में टीवीएस मोटर्स की ओर से नए उत्पाद को लॉन्च किया गया है। टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी को किस तरह की खासियत और रेंज के साथ लॉन्च किया गया है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में निजी वाहनों के साथ कमर्शियल वाहनों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई वाहन निर्माताओं की ओर से नए वाहनों को पेश और लॉन्च किया जा रहा है। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टीवीएस मोटर्स की ओर से 21 अगस्त को ही नए तीन पहिया इलेक्ट्रिक कार्गो वाहन TVS King Kargo HD EV को लॉन्च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत, बैटरी और रेंज को दिया गया है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च हुआ TVS King Kargo HD EV

टीवीएस मोटर्स की ओर से कमर्शियल वाहन सेगमेंट में नए तीन पहिया कार्गो वाहन के तौर पर TVS King Kargo HD EV को लॉन्च कर दिया गया है।

क्या है खासियत

निर्माता की ओर से इस स्कूटर में एलईडी लाइट्स, 200 एमएम डिस्क ब्रेक, 235 एमएम ग्राउंड क्लियरेंस, 26 कनेक्टिड फीचर, फुल रोल डाउन विंडो, तीन ड्राइविंग मोड्स जैसे फीचर्स को दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 500 एमएम वाटर वेडिंग क्षमता, रूफ ट्रिम विकल्प, 28.7 फीसदी की ग्रडिबिलिटी, 6.6 फीट लोडिंग कैपेसिटी को भी दिया गया है।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर

टीवीएस की ओर से TVS King Kargo HD EV में 8.9 KWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिसे फुल चार्ज करने के बाद स्कूटर को 156 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसके साथ ही इसमें दी गई बैटरी से इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड से चलाया जा सकता है। इस तीन पहिया इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0-30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6.9 सेकेंड में चलाया जा सकता है।

कितनी है कीमत

निर्माता की ओर से TVS King Kargo HD EV को भारतीय बाजार में 3.85 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है।

महिंद्रा BE6 बैटमैन संस्करण की बुकिंग कराने वालों के लिए अच्छी खबर, 300 की जगह अब 999 यूनिट्स की डिलीवरी होगी

महिंद्रा BE6 बैटमैन संस्करण महिंद्रा की ओर से BE6 को हाल में ही बैटमैन एडिशन के साथ लॉन्च किया गया है। इस खास एडिशन को अगर आप भी बुक करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए निर्माता की ओर से अच्छी खबर आ गई है। किस तरह की जानकारी निर्माता की ओर से दी गई है।

नई दिल्ली। महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले ही Mahindra BE 6 के Batman Edition को लॉन्च किया गया है। इस एसयूवी को सीमित संख्या में ही ऑफर किया गया था। लेकिन अब इसकी कितनी यूनिट्स को बाजार में ऑफर किया गया है। इसकी क्या खासियत हैं। कितनी रेंज है और किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra ने लॉन्च किया है BE6 का Batman Edition

महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में अगस्त में ही इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6 के Batman Edition को लॉन्च किया गया है। इस एसयूवी की सीमित संख्या में ही यूनिट्स को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया था।

कितनी यूनिट्स मिलेंगी

निर्माता ने इस एडिशन के लॉन्च के समय जानकारी दी थी कि इसकी सिर्फ 300 यूनिट्स को ही बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन अब इसकी संख्या को 300 यूनिट्स से बढ़ाकर 999 यूनिट्स तक कर दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स

Mahindra BE 6 Batman EditioN को दमदार और प्रभावशाली लुक देने के लिए इसे खास साटिन ब्लैक रंग में तैयार किया गया है। गाड़ी के फ्रंट दरवाजों पर कस्टम Batman डिकल, और पीछे की तरफ 'The Dark Knight' की बैजिंग दी गई है। इसके अलावा, हब कैप्स, फ्रंट फेंडर्स और रियर बंपर पर भी Batman का लोगो भी दिया गया है। इसमें 20 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

कितनी है कीमत

Mahindra BE 6 के बैटमैन एडिशन को भारतीय बाजार में 27.79 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसकी बुकिंग को 23 अगस्त से शुरू किया जाएगा। जिसके बाद इसे 21 हजार रुपये में ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक करवाया जा सकता है। बुकिंग की पुष्टि होने के बाद सभी लोग अपनी पंसद के नंबर को 001 से 999 के बीच चुन सकते हैं। 20 सितंबर को इंटरनेशनल Batman Day से इसकी एसयूवी के खास एडिशन की डिलीवरी को शुरू किया जाएगा।

जीप ने रैंगलर की 80 हजार मॉडल को किया रिकॉल, कंपनी ने बताई ये वजह

जीप ने 80000 Wrangler SUV को रिकॉल किया है। इन मॉडलों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) में समस्या मिली है जहाँ एक केबल दबने से TPMS काम करना बंद कर सकता है। कंपनी ने इस समस्या का कारण असेंबली में हुई गलती को बताया है। प्रभावित मालिकों को डीलरशिप पर मुफ्त में केबल बदलने का निर्देश दिया गया है। भारत में अभी तक रिकॉल जारी नहीं किया गया है।

नई दिल्ली। Jeep ने अपनी करीब 80,000 Wrangler SUVs को रिकॉल किया है। यह कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। इसके मॉडलों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) में समस्या देखने के लिए मिली है। इसमें एक केबल है, जिसके दबने की आशंका है। इसके दबने की वजह से TPMS काम करना बंद कर सकता है। कंपने ने इस समस्या का कारण असेंबली में हुई एक गलती को बताया है।

क्या है खराबी?

नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) के अनुसार, FCA US ने पिछले साल अक्टूबर में एक जांच शुरू की थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कुछ Jeep Wrangler में टायर प्रेशर की चेतावनी लाइट क्यों जल रही थी। यह जांच महीनें तक चली, लेकिन इस साल जुलाई में कंपनी ने आखिरकार एक निर्माण संबंधी समस्या का पता लगाया जिसके कारण केबल दब जाती थी।

इस जांच में पाया गया कि रिमोट रिमोट स्टार्ट एंटीना केबल को बाएं रियर सीटबेल्ट रिट्रैक्टर ब्रैकेट के नीचे दबाया जा सकता है, जिसकी वजह से TPMS कम टायर प्रेशर का पता नहीं लगा पाता। ऐसी स्थिति में, टायर प्रेशर की चेतावनी लाइट जलती रहती है।

इसी वजह से Jeep ने अमेरिका में 78,989 Wrangler को रिकॉल करने का फैसला किया, जिसमें 2024 और 2025 मॉडल वर्ष की गाड़ियां शामिल हैं। हालांकि, Jeep का मानना है कि रिकॉल की गई Wrangler में से केवल एक प्रतिशत में ही यह खराबी है, जो कि लगभग 790 यूनिट्स के बराबर है।

क्या होगा समाधान?

Jeep की तरफ से रिकॉल की गई सभी मॉडलों के मालिकों को अपने वाहन को डीलरशिप पर ले जाने का निर्देश दिया जाएगा। वहां, एक तकनीशियन रिमोट स्टार्ट एंटीना केबल का टेस्ट किया जाएगा और अगर जरूरत हो, तो इसे मुफ्त में बदल दिया जाएगा। Jeep अगले महीने की शुरुआत में संभावित रूप से प्रभावित मालिकों को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देगी, लेकिन डीलरों को भेजी गई नोटिस से पता चलता है कि अभी तक कोई समाधान उपलब्ध नहीं है।

भारत में ऑफर करती है ये गाड़ियां

भारत में भी Jeep Wrangler के अलावा Compass, Meridian और Grand Cherokee जैसे मॉडल की बिक्री की जाती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में बिकने वाली Wrangler के लिए कोई रिकॉल जारी नहीं किया है।

महिंद्रा विजन एस टेस्टिंग के दौरान दिखाई दी, बेहतरीन फीचर्स के साथ जानें कब होगी लॉन्च

महिंद्रा विजन एस भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra Vision S को टेस्टिंग के दौरान हाल में ही देखा गया है। इस दौरान क्या जानकारी सामने आई है। किस तरह के फीचर्स के साथ इसे कब तक लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में महिंद्रा की ओर से 15 अगस्त को ही Mahindra Vision S को पेश किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी को हाल में ही टेसटिंग के दौरान देखा गया है। एसयूवी की क्या नई जानकारी सामने आई है। इसे किस तरह के फीचर्स के साथ कब तक लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra Vision S की हो रही टेस्टिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा अपनी नई एसयूवी में से एक विजन एस की टेसटिंग कर रही है। निर्माता की ओर से हाल में ही 15 अगस्त को इसके कॉन्सेप्ट वर्जन को पेश किया गया है। जिसके बाद इसके प्रोडक्शन के नजदीक वाले वर्जन को टेस्ट के दौरान देखा गया है।

क्या मिली जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के प्रोडक्शन वर्जन के पास वाली यूनिट को पूरी तरह से ढंका गया था। जिस कारण इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट की तरह बॉक्सी डिजाइन, सपाट रूफलाइन, चौकोर व्हील आर्च जैसा डिजाइन दिया गया है। कॉन्सेप्ट वर्जन की तरह ही इसमें भी रियर में स्पेयर व्हील लगाया गया है।

कैसा होगा इंटीरियर

जानकारी के मुताबिक एसयूवी का इंटीरियर भी इसके कॉन्सेप्ट वर्जन की तरह ही हो सकता है। लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। एसयूवी में फीचर्स के तौर पर बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम इंटीरियर को दिया जा सकता है।

कब होगी लॉन्च

निर्माता की ओर से अभी इसके प्रोडक्शन के नजदीक वाले वर्जन को टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके लॉन्च को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि इसे 2027 तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

कितनी होगी कीमत

महिंद्रा की ओर से जब एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा तभी कीमत की जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस एसयूवी को 10 से 20 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के बीच लॉन्च किया जा सकता है।

नई रेनॉल्ट किगर का आया टीजर, जानें क्या कुछ मिलेंगे नए फीचर्स

रेनॉल्ट ने अपनी Kiger कॉम्पैक्ट SUV का 2025 मॉडल टीजर जारी किया है जिसमें मामूली बदलाव और मौजूदा डिजाइन को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है। 2025 Renault Kiger में नया लाइम ग्रीन पेंट शेड और 2D डायमंड लोगो देखने को मिलेगा। इसमें नया ग्रिल बम्पर और LED टेल लैंप्स भी हो सकते हैं। इंटीरियर में सॉफ्ट-टच मटेरियल और 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा।

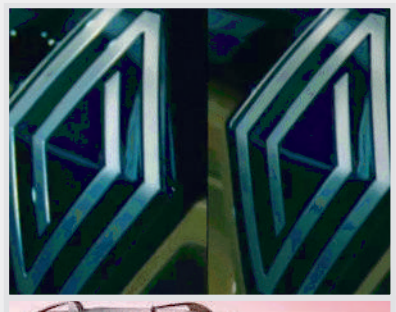

रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Kiger के 2025 मॉडल का टीजर जारी किया है। यह टीजर यह संकेत देता है कि कंपनी ने बड़े बदलावों के बजाय मौजूदा डिजाइन और फीचर्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि 2025 Renault Kiger को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा?

2025 Renault Kiger का डिजाइन

इसके टीजर में नई लाइम ग्रीन पेंट शेड देखने के लिए मिला है। इसके फ्रंट में कंपनी का नया 2D डायमंड लोगो भी दिखा है। Renault Triber की तरह, इसमें नया डिज़ाइन किया गया ग्रिल, नए बंपर, पतली हेडलाइट्स और एक LED DRL स्ट्रिप मिल सकती है। इसके पीछे की तरफ नई LED टेल लैंप्स के साथ C-आकार की टेल लाइट्स दिए जा सकते हैं।

2025 Renault Kiger का इंटीरियर

इसमें सॉफ्ट-टच मटेरियल और नई अपहोल्स्ट्री टोन दिया जा सकता है। इसके डैशबोर्ड के लेआउट में भी कुछ मामूली बदलाव होने की उम्मीद है। नए फीचर्स के रूप में -इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए सभी वेरिएंट में छह एयरबैग स्टैंडर्ड के रूप में दिए जा सकते हैं।

2025 Renault Kiger का इंजन

इसे दो इंजन ऑप्शन के साथ लाया जा सकता है। इसमें 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। यह इंजन मैनुअल, एएमटी (AMT) और सीवीटी (CVT) ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ पेश किए जा सकते हैं।

कितनी होगी कीमत?

नई Renault Kiger की कीमतें मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 6.2 लाख रुपये से लेकर 11.5 लाख रुपये तक हो सकती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Hyundai Venue और Kia Sonet जैसी गाड़ियों से देखने के लिए मिलता है।।

शिक्षा और प्रौद्योगिकी: एक उज्जवल भविष्य के लिए आदिवासी लड़कियों को सशक्त बनाना

विजय गर्ग

शिक्षा और प्रौद्योगिकी आदिवासी लड़कियों को सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके उन्हें काफी सशक्त बना सकती है। यह सशक्तिकरण न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में सुधार करता है बल्कि उनके समुदायों के समग्र विकास में भी योगदान देता है। शिक्षा और प्रौद्योगिकी का प्रभाव शिक्षा और प्रौद्योगिकी एक साथ परिवर्तन के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। आदिवासी लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके, यह उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है और उनके समुदायों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ा सकता है। तथा

गरीबी के चक्र को तोड़ता है: शिक्षा आदिवासी लड़कियों को कौशल प्रदान करती है जो उनके रोजगार के अवसरों और कमाई की क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे उनके परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिलती है।

स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार: शिक्षित महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण सहित स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में अधिक पता है, स्वस्थ परिवारों के लिए अग्रणी और शिशु मृत्यु दर में कमी।

लिंग समानता को बढ़ावा देता है: उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाकर, शिक्षा और प्रौद्योगिकी पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है, जिससे अधिक समानता होती है।

सांस्कृतिक संरक्षण: प्रौद्योगिकी का उपयोग डिजिटल अभिलेखागार, शैक्षिक सामग्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाकर आदिवासी भाषाओं, परंपराओं और कलाओं को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। चुनौतियां और समाधान सकारात्मक परिवर्तन की क्षमता के बावजूद, दूर करने के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ये चुनौतियां अक्सर भौगोलिक अलगाव, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों में निहित होती हैं।

भौगोलिक अलगाव: कई आदिवासी समुदाय स्कूलों, बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक सीमित पहुंच के साथ दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं।

समाधान: दूरदराज के क्षेत्रों में आवासीय स्कूलों की स्थापना और अलग-अलग गांवों में शिक्षा देने के लिए मोबाइल शिक्षण इकाइयों या सौर-संचालित डिजिटल शिक्षण केंद्रों का उपयोग करें।

आर्थिक बाधाएं: गरीबी कई परिवारों को शिक्षा पर काम को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती है, जिससे लड़कियों के बीच उच्च ड्रॉपआउट दर होती है।

समाधान: परिवारों को अपनी बेटियों को स्कूल में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें। कौशल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करें जिससे तत्काल आर्थिक लाभ हो सकते हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं: प्रारंभिक विवाह, पितृसत्तात्मक मानदंड, और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम की कमी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोक सकती है।

समाधान: द्विभाषी प्राइमर और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शैक्षिक सामग्री विकसित करना जो आदिवासी भाषाओं और परंपराओं को दर्शाता है। समुदाय के नेताओं और बड़ों को विश्वास बनाने और लड़कियों की शिक्षा के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए शामिल करें। सफल पहल भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में कई पहलों ने आदिवासी लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): भारत सरकार ने इन स्कूलों को दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया है।

डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म: SWAYAM और ई-पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और संसाधन प्रदान करते हैं, जो कई विषयों तक पहुंच प्रदान करते हैं।

आईसीटी-सक्षम शिक्षा: केरल में VICTERS जैसे टेलीविजन चैनलों का उपयोग करने वाले कार्यक्रमों ने दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों को शैक्षिक सामग्री देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग किया है, विशेष रूप से स्कूल बंद होने के दौरान।

वित्तीय समावेशन: प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और महिला उद्यमियों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन पहल जैसी योजनाओं ने आदिवासी महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में भी मदद की है।

आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को प्राथमिकता

विजय गर्ग

पंद्रह अगस्त पर लाल किले से प्रधानमंत्री का राष्ट्र के लिये संबोधन महज एक औपचारिकता नहीं होता, बल्कि समकालीन राष्ट्रीय चुनौतियों व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर सरकार की रीति-नीति का परिचय होता है। आने वाले समय की योजनाओं का खाका और राष्ट्रीय संकल्पों की बानगी होता है। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन निस्संदेह, इन्हीं रीति-नीतियों का विस्तार था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ के बीच स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पर बल दिया। साथ ही यह भी दोहराया कि विश्व में पहुंच बनाने के लिये हमारी प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की होनी चाहिए। उन्होंने रक्षा उत्पाद निर्माण को वरीयता देने की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप आ जाएगी। निश्चय ही यह कामयाबी हमारी तकनीकी व सुरक्षा जरूरतों के लिये महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन पर भी जोर दिया, जो रक्षा उत्पादों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पं. नेहरू के बाद लगातार बारहवीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने वाले मोदी का यह संबोधन अब तक का सबसे लंबा अवधि वाला था। लेकिन समकालीन चुनौतियों के मद्देनजर यह तार्किक था। उन्होंने उर्वरकों, परमाणु ऊर्जा, जीएसटी, अर्थव्यवस्था के लिये रिफोर्म टास्क फोर्स के गठन, अंतरिक्ष अभियान जैसे तमाम मुद्दों को संबोधित किया। निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता के प्रयासों से जहां हम अपने आर्थिक लक्ष्य पा सकते हैं, वहीं हम अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर सकने में सक्षम हो सकेंगे।

निश्चित रूप से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के परिदृश्य के बीच भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिये उत्पादन क्षेत्र में आशातीत वृद्धि करनी होगी। तभी हम चीन के साथ लगातार बढ़ते व्यापार असंतुलन को दूर कर पाने में किसी हद तक सफल हो सकते हैं। फिर हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के लिये चुनौती बनती घुसपैठ की समस्या को भी संबोधित किया और उच्च शक्ति वाला डेमोग्राफी मिशन चलाने की बात कही। दरअसल, आज घुसपैठ जनसांख्यिकीय बदलाव की स्थिति तक पहुंच गई है। देश में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ डेढ़ करोड़ बतायी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र करके देश को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आने वाले दशक में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के मुकाबले को उन्होंने 'सुदर्शन चक्र' नामक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करने की बात कही। जिसमें रक्षा उत्पादों का आधुनिकीकरण भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि बाह्य दबाव अस्वीकार करके किसानों, पशुपालकों व मछुआरों के हितों की रक्षा की जाएगी। उनका मानना था कि हम इतने मजबूत बनें कि चुनौतियां हमारी सफलता का मार्ग तय करें। कुल मिलाकर उन्होंने देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को संबोधित करते हुए समाधान की राह का विस्तार से जिक्र किया। विश्वास किया जाना चाहिए कि देश के आंतरिक मोर्चे पर उन्होंने किसानों के संरक्षण व प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के मुद्दे पर जो कहा, उसे यथाशीघ्र हकीकत बनाया जाएगा।

खुली किताब

विजय गर्ग

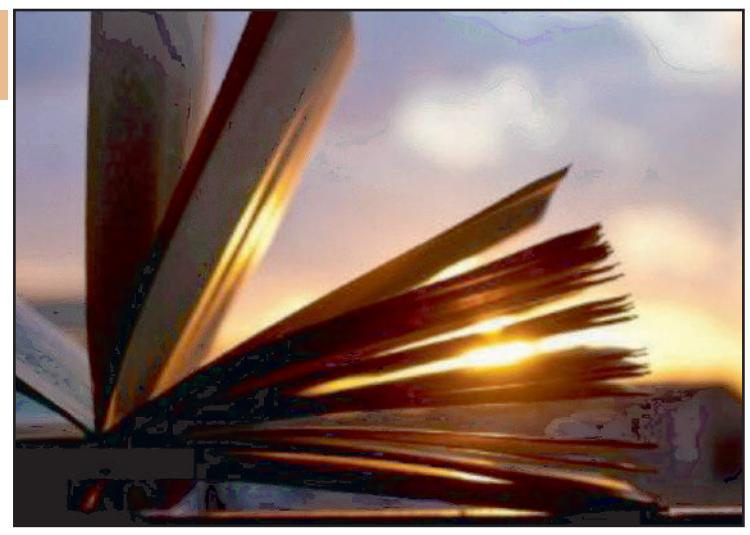

हम जिस बात की चिंता करते देखे-सुने जाते हैं क्या वे हमारी वास्तविक चिंताएं हैं? यह सवाल इसलिए कि अगर ये चिंताएं वास्तविक होतीं तो हम उस चिंता की जड़ को सामने देख कर उसके पेड़ बन जाने व उसके फलने-फूलने का इंतजार नहीं करते।

इन दिनों हर कोई कृत्रिम मेधा यानी 'एआइ' की चिंता करता दिख जाएगा। इसी समय हमारे बीच फैसला आता है कि देश का शीर्ष शिक्षा बोर्ड अब दसवीं की परीक्षा 'खुली किताब' से लेगा। इसके पहले भी शिक्षा को लेकर बहुत तरह के फैसले हुए हैं जिसे लेकर आम लोगों के बीच न्यूनतम बहस हुई है। शिक्षा वैसे भी आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है लेकिन इससे जुड़ी बहसें खास अकादमिक तबके तक ही सिमट जाती हैं। ताजा फैसला नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। पर इस शिक्षा नीति की समग्रता पर ही कितनी बात हुई है ? अब हमारी शिक्षा नीति का पूरा लक्ष्य गुणवत्ता से ज्यादा संख्या पर है। आम भाषा में कहें तो इसका मतलब है शिक्षितों का आंकड़ा बढ़ाना। हम दुनिया को बता सकें कि हमारे यहां किसी तरह की अशिक्षा नहीं है।

किसी भी देश की शिक्षा नीति वहां के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात का आईना होती है । फिलहाल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किसी तरह 'पास' कर देने की नीति समाज में किसी तरह का ढांचागत बदलाव नहीं ला सकते हैं । अभी तो यह हाल हो गया है कि अगर बच्चा फेल करने के लिए बहुत मेहनत करेगा तभी वह फेल हो सकता है। वरना अब शिक्षकों के हाथ में बहुत सारी शैक्षणिक तकनीक है। आंतरिक मूल्यांकन भी इसी संतुलन बिठाने की तकनीक बन चुका है, जिसमें कभी पूरे के पूरे अंक दे दिए जा सकते हैं।

अब बात है खुली किताब से परीक्षा देने की। किताब ने क्या सीख दी, यह जानने के लिए किताब को बंद करना होगा। किताब बंद करने के बाद ही हमारा दिमाग सोचेगा कि किताब में क्या, क्यों, कैसा और कितना था। बात तोता रटंत विद्या की नहीं, बात विषयवस्तु को आत्मसात करने की है। किताब में चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि किताब बंद होने पर आप उन चीजों का मंथन कर सकें। हिंदी की किताब में 'हवा हूं, हवा मैं बसंती हवा हूं' पढ़ने के बाद कोई बच्चा क्या चल रही बसंती हवा के बारे में सोचेगा ? क्या वह अन्य मौसमों की हवा और बसंती हवा के बीच में सच फर्क करेगा? वह यह सब तभी करेगा जब उसे कोई ऐसा मिले जो उसे उस कविता को जीवन की गतिविधि की तरह पढ़ाए। स्कूल से निकल कर, बाहर की हवा में पहुंच कर वह बसंती हवा की खुराक ले सके।

बड़ी जनसंख्या और आर्थिक विषमताओं वाले हमारे देश में शिक्षा और स्कूलों के अंकों का अंतर अनुशासनात्मक संबंध है। स्कूल के अंक मतलब नौकरी। अब अगर परीक्षा के अंकों के लिए किताबें पढ़ने व समझने की जरूरत नहीं रहे तो फिर कितने बच्चों को उनके माता-पिता सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे ? कितने अभिभावक यह सोच पाएंगे कि सिर्फ परीक्षा में अंकों के लिए ही किताबें पढ़नी जरूरी नहीं हैं? एक बेहतर नागरिक बनने के लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए और उसमें लिखी चीजें हमारे स्मरण में रहनी चाहिए।

स्कूल का काम सिर्फ परीक्षाएं लेना नहीं, बल्कि सिखाना है। किताबों का काम सिर्फ परीक्षाएं पास करवाना नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा देना है। पढ़े गए का मूल्यांकन ही परीक्षा है। क्या हम उस पीढ़ी तक पहुंच गए हैं जो किताबों के पन्ने खुले होने के बावजूद सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएगी ? खुली किताब पर एक खुली बहस तो हो जानी चाहिए।

'जलवायु परिवर्तन से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पक्षियों की संख्या 38 फीसद तक कम हुई '

विजय गर्ग

जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ रही प्रचंड गर्मी की वजह से 1980 के बाद से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पक्षियों की संख्या में 25 से 38 फीसद तक की कमी आई है, जबकि कुछ प्रजातियों की संख्या आधी से भी कम रह गई है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। 'नेचर' पत्रिका में सोमवार को इस संबंध में नया अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया गया जिसे 'पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फार क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च' (पीआइके), क्वींसलैंड विश्वविद्यालय और 'बार्सिलोना सुपरकंप्यूटिंग सेंटर' (बीएससी) के वैज्ञानिकों ने किया है। पीआइ में अतिथि अनुसंधानकर्ता और बीएससी में अनुसंधानकर्ता एवं अनुसंधान पत्र के प्रमुख लेखक मैक्सिमिलियन कोट्ज ने कहा, 'पक्षियों की संख्या में यह कमी चौंका देने वाली है। पक्षी पानी की कमी और गर्मी के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं । अत्यधिक गर्मी के कारण अत्यधिक मृत्यु दर, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन व्यवहार में बदलाव और संतानों के जीवित रहने की दर में कमी आती है।'

अध्ययन में पाया गया कि मौजूदा समय में उष्णकटिबंधीय पक्षी साल में औसतन 30 दिन भीषण गर्मी का सामना करते हैं, जबकि चार दशक पहले यह संख्या केवल तीन दिन थी । कुल मिलाकर, अब वे 1980 की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे हैं।

अध्ययन के मुताबिक अनुसंधानकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों को विभिन्न माडल के साथ संयोजित किया और गर्मी एवं वर्षा पर ध्यान केंद्रित किया तथा इस प्रकार दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के पक्षियों की संख्या पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान की। अध्ययन में कहा गया है, 'मानव जनित जलवायु परिवर्तन के बिना की स्थिति और 1950 से 2020 बीच में रिकॉर्ड प्रचंड गर्मी की ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर उष्णकटिबंधीय पक्षियों की तुलना की गई और पाया गया कि इनकी संख्या में 25-38 फीसद की कमी आई है।'

अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक पक्षियों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दर्ज की गई, लेकिन लगभग हर क्षेत्र में इनकी संख्या कम हुई है जिसके लिए अत्यधिक गर्मी को सबसे बड़ा कारण माना गया है। कोट्ज ने कहा, 'बढ़ता तापमान वास्तव में प्रजातियों को उस सीमा से बाहर धकेल रहा है, जिसके लिए वे स्वाभाविक रूप से अनुकूलित हो चुके हैं और वह भी बहुत कम समय में।'

अब तक, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को वनों की कटाई जैसी प्रत्यक्ष मानवीय गतिविधियों से होने वाले नुकसान से अलग करना चुनौतीपूर्ण रहा है। पीआइके ने एक बयान में कहा कि अनुसंधान दल की विधियों ने उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाया, जिससे पता चला कि निचले अक्षांश वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी पक्षियों की संख्या में गिरावट में वनों की कटाई और आवास विनाश की तुलना में अधिक योगदान दे रही हैं।

बयान में कहा गया है कि इससे हाल में अमेजन और पनामा के अछूते उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पक्षियों की संख्या में आई भारी गिरावट को समझने में मदद मिल सकती है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के सह-लेखक तात्सुया अमान ने कहा, 'संरक्षण के संदर्भ में, यह कार्य हमें बताता है कि संरक्षित क्षेत्रों और वनों की कटाई को रोकने के अलावा, हमें उन प्रजातियों के लिए रणनीतियों पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है जो अत्यधिक गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, ताकि उनकी अनुकूलन क्षमता को अधिकतम किया जा सके।' कोट्ज ने कहा, 'अंततः, मानव गतिविधियों से होने वाला उत्सर्जन ही इस समस्या के केंद्र में हैं। हमें इन्हें यथाशीघ्र

मन की दौड़

उन्नीसवीं सदी के महान रूसी लेखक लियो टॉलस्टाय ने तो यहां तक कह डाला कि किसी मूर्ख को भी कोई नई बात समझाई जा सकती है, बशर्ते कि उसने उस विषय पर पहले से ही अपना कोई मत न बना रखा हो, लेकिन किसी मूर्धन्य विद्वान को वही बात समझाना लगभग असंभव है जिसने उस विषय पर अपना मत दृढ़ कर रखा हो। सच, झूठ, विचार और विश्वास की यह कहानी मन की सीमाओं को रेखांकित करती है और हमें यह सबक देती है कि रिश्तों में विश्वास को बहुत महत्व है। यदि सामने वाले व्यक्ति को हम पर विश्वास न हो तो हम चाहे जो कर लें, अपनी बात उसे न समझा सकते हैं, न मनवा सकते हैं। पति-पत्नी के रिश्तों में दुराव अक्सर इसीलिए आता है जो शुरू में कलह का और अंतत: तलाक का कारण बनता है। स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ने आज से अढ़ाई हजार साल पहले ही वह कह डाला जिसे आधुनिक मनोविज्ञान स्वीकार कर रहा है

गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कथा बहुत शिक्षाप्रद है। उनके सभी शिष्य उनके आसपास बैठे थे, तभी गांव का एक व्यक्ति आया और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने के बाद बोला कि हे भंते, मेरा विश्वास है कि भगवान हैं, भगवान ही इस दुनिया को चलाते हैं और उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कृपया बताइये कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है? महात्मा बुद्ध अपनी चिर-परिचित शैली में मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में बोले कि तुम ठीक कहते हो। भगवान तो हैं ही, वे ही पालनहार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं और वे ही दुनिया को चला रहे हैं। उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और खुश होकर चला गया। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरा पक्का विश्वास है भगवान-वगवान सब झूठी बातें हैं, दिखावा है, भ्रम है और लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। यह सिर्फ अंधविश्वास है और मनुष्य के पतन का कारण है। आप क्या कहते हैं। बुद्ध फिर मुस्कुराए और उतनी ही शांति से बोले कि मित्र तुम ठीक कहते हो। लोग भ्रम में पड़े हैं, अंधविश्वास का शिकार हैं और यूं ही मंदिरों-तीर्थों के चक्कर काट रहे हैं। उस व्यक्ति ने भी बुद्ध को प्रणाम किया और खुश होकर चला गया। कुछ और देर बीती तो एक और व्यक्ति आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और चुपचाप उनके चरणों में बैठ गया। वह लगातार वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध ने अपनी मीठी मुस्कान के साथ बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वह व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से उनके चरणों में झुका और बोला कि मैं धन्य हुआ, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। इतना कहकर वह भी खुशी-खुशी चला गया। गौतम बुद्ध के इस अनोखे व्यवहार से उनके शिष्य असमंजस में पड़ गए। महात्मा बुद्ध का व्यवहार उनकी समझ में नहीं आ रहा था। दो व्यक्तियों का सवाल एक ही था, पर उत्तर बिल्कुल अलग-अलग थे, और सिर्फ अलग ही नहीं थे, बल्कि एक-दूसरे के विपरीत थे।

यही नहीं, तीसरे व्यक्ति ने न कुछ पूछा न बुद्ध ने कुछ बताया, फिर भी वह यह कहकर गया कि उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया। उनके प्रधान शिष्य आनंद से आखिर रहा नहीं गया और उसने बुद्ध के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर ही दी। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों की शंका का समाधान करते हुए कहा कि पहले दो व्यक्ति खुद को बुद्धिमान मानते थे, वे अपने ही पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे और वे कुछ जानने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने विचारों की पुष्टि चाहते थे। यह स्पष्ट है कि अभी वे सीखने के लिए तैयार ही नहीं थे, वे सीखने के योग्य पात्र ही नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें कुछ सिखाने या बताने की कोशिश नहीं की। मैंने उनके विचारों का समर्थन सिर्फ इसलिए किया ताकि वे जब कभी सीखने के योग्य बनें तो अपनी इसी गलती को दोबारा न दोहराएं। जो तीसरा व्यक्ति आया, वह शांति से बैठा रहा, यहां व्याप्त शांत तरंगों से अपने विचारों को शुद्ध करता रहा, और अंततः समझ गया कि सत्संग और मौन भक्ति के दो महत्वपूर्ण शुरुआती चरण हैं। आज वह मौन का पाठ पढ़ कर गया है। मौन की साधना ने उसके मन को स्थिर किया है। वह अपनी खोज जारी रखने में समर्थ हो गया है। यह सच है कि अभी उसकी खोज पूरी नहीं हुई, पर वह दृढ़ कदमों से खोज की राह पर निकल चुका है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने जो आगे कहा, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमारा मन जब अहंकार से ग्रसित होता है तो वह सत्य नहीं चाहता, वह सत्य की खोज का जिज्ञासू नहीं होता, वह अपने ही विचारों का समर्थन चाहता है। हम अपने अहंकार को पोषित करते रहना चाहते हैं। मन की दौड़ बस यहीं तक है। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति हमें पसंद हो और वह हमसे बार-बार, लगातार असहमत होता रहे तो धीरे-धीरे हम उसे नापसंद करना शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुद्धिहीन हो, या हमें नापसंद हो लेकिन वह लगातार हमारी बातों से सहमति जताता रहे तो धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ ही जाती है कि हमारी नापसंदगी दूर हो जाती है और हम उसकी सारी खामियों के बावजूद उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं। मन की दौड़ का आलम यह है कि यदि किसी भी विषय पर हमारी कोई एक निश्चित विचारधारा हो तो हमारे सामने कोई ऐसे नए तथ्य आएं जो हमारी स्थापित विचारधारा के विपरीत हों तो हम इस कोशिश में जुट जाते हैं कि अपने स्थापित विचारों के समर्थन में हम क्या कर सकते हैं।

यानी, हम तथ्य होने के बावजूद नए तथ्यों को स्वीकार करने के बजाय हमारी पहली कोशिश यही होती है कि हम अपनी स्थापित विचारधारा को ही सही सिद्ध कर सकें। इस पर भी तुर्रा यह कि यदि नए विचार किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आए हों जो व्यक्ति हमें नापसंद हो तो हम नए विचारों को बिना जांचे-परखे ही अस्वीकार कर देते हैं, फिर तो हम अक्सर उन्हें समझने, जानने या जांचने की कोशिश तक भी नहीं करते। मजे की बात यह है कि वही नए तथ्य, जो हमारे स्थापित विश्वास के अनुरूप नहीं थे, यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति बताए जिसे हम बहुत पसंद करते हैं तो अक्सर हम अपने विचार बदल लेते हैं। यानी, विचारधारा बदलने में या विचारों को बदलने में जो भूमिका दरअसल तथ्यों की होनी चाहिए थी, वह पसंदगी और नापसंदगी को हासिल है, विश्वास और अविश्वास को हासिल है। हम तथ्यों के कारण विचार नहीं बदलते, अपनी पसंद वाले व्यक्ति के कारण विचार बदलते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के कारण विचार बदल लेते हैं जिस पर हमें विश्वास हो।

उन्नीसवीं सदी के महान रूसी लेखक लियो टॉलस्टाय ने तो यहां तक कह डाला कि किसी मूर्ख को भी कोई नई बात समझाई जा सकती है, बशर्ते कि उसने उस विषय पर पहले से ही अपना कोई मत न बना रखा हो, लेकिन किसी मूर्धन्य विद्वान को वही बात समझाना लगभग असंभव है जिसने उस विषय पर अपना मत दृढ़ कर रखा हो। सच, झूठ, विचार और विश्वास की यह कहानी मन की सीमाओं को रेखांकित करती है और हमें यह सबक देती है कि रिश्तों में विश्वास को बहुत महत्व है। यदि सामने वाले व्यक्ति को हम पर विश्वास न हो तो हम चाहे जो कर लें, अपनी बात उसे न समझा सकते हैं, न मनवा सकते हैं। पति-पत्नी के रिश्तों में दुराव अक्सर इसीलिए आता है जो शुरू में कलह का और अंततः तलाक का कारण बनता है। स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ने आज से अढ़ाई हजार साल पहले ही वह कह डाला जिसे आज का आधुनिक मनोविज्ञान स्वीकार कर रहा है। हम इस साधारण से दिखने वाले महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लें तो हमारा सारा जीवन ही बदल सकता है।

नई दवाएं खोजने में एआइ बन रही मददगार

विजय गर्ग

दुनिया में खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया में दवा प्रतिरोधी क्षमता लगातार बढ़ रही है। दवा प्रतिरोध बढ़ने से एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो रही हैं। दवा प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए विज्ञानी नई एंटीबायोटिक दवाएं विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अब वे एआइ की भी मदद ले रहे हैं। मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (एमआइटी) के शोधकर्ताओं ने गोनोरिया और एमआरएसए जैसे दवा - प्रतिरोधी बैक्टीरिया को लक्षित करने वाले नई एंटीबायोटिक दवाएं बनाने करने के लिए जेनरेटिव एआइ का उपयोग किया है। ये यौगिक मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना बैक्टीरिया को मार देते हैं। नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास में यह एक बड़ी सफलता है। शोधकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त एआइ सिस्टम ने 3.6 करोड़ से अधिक संभावित यौगिकों का विश्लेषण किया। उसने नए अणु उत्पन्न किए जिनमें मौजूदा दवा प्रतिरोध को दरकिनार करने वाले तंत्र मौजूद थे। पारंपरिक तरीकों की तुलना में इस विधि से दवाएं खोजने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। इससे दवा के विकास की समय सीमा वर्षों से घटकर महीनों में आ जाती है। 'सुपरबग' बैक्टीरिया में दवा प्रतिरोध एक बढ़ता हुआ वैश्विक खतरा है। वैश्विक स्तर पर यह अनुमान है कि दवा - प्रतिरोधी जीवाणु संक्रमण प्रति वर्ष लगभग 50 लाख मौतों का कारण बनते हैं।

एमआइटी के शोधकर्ताओं ने मौजूदा रासायनिक यौगिकों के विशाल संग्रह की जांच के लिए एआइ की शक्ति का उपयोग किया है। एआइ ने संभावित अणुओं की एक सूची को स्कैन किया और भविष्यवाणी की कि कौन से अणु एंटीबायोटिक के रूप में काम कर सकते हैं। एआइ ने उन संरचनाओं से बचने की कोशिश की, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस कार्य से कई आशाजनक दवाएं सामने आई हैं, जिनमें हैलिसिन और एबाउसिन शामिल हैं। दोनों नए एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की उन किस्मों को मारने में सक्षम थे जिनका मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज करना मुश्किल होता जा रहा है। एनजी 1 नामक एक नई दवा गोनोरिया को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है । यह एक यौन संचारित संक्रमण है, जो एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ तेजी से प्रतिरोध विकसित कर रहा है। कुछ मामलों में गोनोरिया का इलाज असंभव होता जा रहा है। दूसरी दवा का नाम डीएन । है । इसे एमआरएसए नामक संक्रमण से निपटने के लिए विकसित किया, जिस पर अब मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता ।

यह उपलब्धि दवा अनुसंधान में एआइ की व्यापक क्षमता को उजागर करती है। छोटी बायोटेक कंपनियां दवा डिजाइन करने, लागत कम करने और चिकित्सा संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआइ का लाभ उठा सकती हैं।

130 वें संविधान संशोधन पर आखिर क्या निर्णय लेगी: संयुक्त संसदीय समिति ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को नया विधेयक पेश किया गया है, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वास्तव में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए विधेयक- संविधान संशोधन, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है।मतलब यह कि अब कानून सबके लिए बराबर होगा। यहां सवाल यह उठता है कि गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति को जब हमारे देश में कोई नौकरी तक नहीं दी जाती है, तो देश के नेताओं के साथ भी ऐसा कुछ प्रावधान क्या नहीं किया जाना चाहिए ? आज हमारे देश में अनेक दागी नेता आसानी से बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन अब इस बिल के लाये जाने के बाद इस परंपरा (दागी जनप्रतिनिधियों के बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री बनने) पर कहीं न कहीं रोक लग सकेगी, यह कदम एक स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है। यहां पाठकों को बताता चलूं विपक्ष ने संविधान संशोधन विधेयक पेश होते ही जोरदार विरोध व हंगामा किया और वैल में आ गए। गौरतलब है कि विपक्षी सांसदों ने विधेयक की प्रतियां तक फाड़ दी और कागज गृह मंत्री शाह की ओर उछाले। दरअसल, इस संबंध में विपक्ष का यह आरोप था कि यह विधेयक उनके खिलाफ लाया जा रहा है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स बतातीं हैं कि बिल के विरोध में टीएमसी सांसद नारे लगाते हुए वैल में भाजपा सांसदों की ओर बढ़े तथा हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल तुरंत शाह की तरफ आ गए और उनके लिए सुरक्षा घेरा बना लिया। बहरहाल, यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि बिल की कॉपी फाड़े जाने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज हुए और सांसदों से ऐसा नहीं करने के लिए कहा। इस दौरान शाह व कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस भी हुई। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान शाह ने पद नहीं छोड़ा था। जवाब में शाह ने कहा कि उन्होंने अरेस्ट होने से पहले ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। शाह ने कहा कि संशोधन कर मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल से सरकार न चला सकें। उन्होंने यह बात कही कि, 'जनता को तय करना होगा कि जेल से सरकार चलाना उचित है या नहीं।' यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि बिल के संबंध में इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह ने कहा कि 'एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने आपको कानून के दायरे में लाने का संविधान संशोधन पेश किया और दूसरी ओर कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकारें चलाने और कुर्सी का मोह न छोड़ने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया।' इतना ही नहीं, अमित शाह ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 39 वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर प्रधानमंत्री के विरूद्ध किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान करने का हवाला देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। हाल फिलहाल, इस विधेयक(130 वां संविधान संशोधन बिल) में यह प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी केंद्रीय/राज्य मंत्री पर ऐसी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, जिनमें पांच साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, और वे लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें इकतीसवें दिन उन्हें अपना पद छोड़ना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद-ब-खुद इस पद से उन्हें हटा दिया जाएगा।ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री की सलाह पर उस केन्द्रीय मंत्री को उसकी गिरफ्तारी के 31वें दिन तक उसके पद से हटा सकते हैं। अगर किसी वजह से देश का प्रधानमंत्री इस पर कोई फैसला नहीं लेता और वो केन्द्रीय मंत्री को बचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो केन्द्रीय मंत्री अपनी गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद इस पद से हट जाएगा और उनसे सारी ज़िम्मेदारी वापस ले ली जाएगी।इसी तरह से अगर प्रधानमंत्री को किसी आपराधिक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो भी खुद-ब-खुद इस पद से हटा दिए जाएंगे। यहां दोनों मामलों में छूट ये होगी कि कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी चाहे तो वो उस नेता को फिर से प्रधानमंत्री या केन्द्रीय मंत्री चुन सकती है. इसी तरह के प्रावधान राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होंगे, जिसके लिए अनुच्छेद 164 में एक नया भाग जोड़ा जाएगा।इसके तहत राज्य सरकार में कोई मंत्री गिरफ्तार होता है तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उस मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं और अगर खुद मुख्यमंत्री ही गिरफ्तार हो जाएं तो उन्हें भी 30 दिनों तक जेल में रहने के बाद 31वें दिन इस पद से हटा दिया जाएगा या उन्हें भी इससे पहले इस्तीफा देना होगा। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि ये बिल प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होता है लेकिन इसमें विधायकों और सांसदों का कोई ज़िक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विधायकों और सांसदों पर अब भी वही नियम लागू होगा, जिसमें उनकी सदस्यता तब तक वैध होती है, जब तक अदालत से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता और उन्हें दो साल या उससे ज्यादा की सज़ा नहीं होती।इस संबंध में सरकार का यह कहना है कि ये बिल संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के चरित्र और आचरण को संदेह से परे रखेगा, जो नेता गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं।उनके इस्तीफे से जनता का विश्वास लोकतंत्र में मजबूत होगा। सरकार ये भी कह रही है कि जब जेल जाकर भी कोई नेता अपने पद को नहीं छोड़ता, तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ था। यहां पाठकों को बताता चलूं कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल करीब पांच महीनों तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया था।इसी तरह सत्येंद्र जैन भी जब डेढ़ साल तक तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था और ना ही अरविंद केजरीवाल ने कभी उनसे इस्तीफा मांगा। सबसे ज्यादा विवाद वी. सेंथिल बालाजी को लेकर हुआ था, जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार में ऊर्जा मंत्री थे।उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और कैश के बदले नौकरी देने का आरोप था। 14 जून 2023 को इंडी(प्रवर्तन निदेशालय) ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बाद भी जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो राज्यपाल आर.एन.रवि ने खुद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था, जिस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच खूब विवाद हुआ। हाल फिलहाल, कहा जा रहा है कि इसी विवाद के बाद केन्द्र सरकार अब ये कानून लेकर आई है।इधर, विपक्ष का इस बिल के संबंध में यह कहना है कि ये बिल भारत के संविधान का उल्लंघन है। इससे कानून का दुरुपयोग होगा और केन्द्र सरकार जिस मुख्यमंत्री को हटाना चाहेगी उसे गिरफ्तार करके 30 दिनों तक जेल में रखा जाएगा, जिससे वो सरकार से हट जाए और विपक्ष की एक बड़ी दलील ये भी है कि दोषी साबित होने से पहले किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री से उसका पद छीनना लोकतंत्र के खिलाफ है और सरकार ने भी विरोध के बाद इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। हाल फिलहाल, यहां यह उल्लेखनीय है कि साल 2013 में यूपीए की सरकार दागी नेताओं को बचाने के लिए एक अध्यादेश(आर्डिनेंस) लाई थी, जिसके अनुसार यदि किसी सांसद को अदालत से सज़ा हो जाती है और ये सज़ा दो साल से ज्यादा है, तो तब भी वो नेता ऊपरी अदालत में अपील दायर करके सांसद बना रह सकता है। ये अध्यादेश दागी सांसद खुद को बचाने के लिए लाए थे, जिसका स्वयं राहुल गांधी ने भी विरोध किया था और कहा था कि ऐसे अध्यादेश को तो फाड़कर फेंक देना चाहिए, लेकिन अब सरकार यह कह रही है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री भी दागी हो जाएं, तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि(मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक) मौजूदा लोकसभा में 543 में से 251 यानी 46 फीसदी सांसद दागी हैं. इनमें भी 27 सांसद ऐसे हैं, जिनके खिलाफ निचली अदालतों में आरोप साबित भी हो चुके हैं। बड़ी पार्टियों में सबसे ज्यादा कांग्रेस के 49 प्रतिशत सांसद दागी हैं और बीजेपी के 39 प्रतिशत सांसद दागी हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा के 170 यानी 31 फीसदी सांसदों पर रेप, हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मुकदमें दर्ज हैं। इनमें बीजेपी के कुल 26 प्रतिशत यानी 63 सांसदों पर संगीन अपराध के आरोप हैं। कांग्रेस के 32 प्रतिशत यानी 32 सांसदों पर आरोप हैं, और समाजवादी पार्टी के 17 और टीएमसी के भी 7 सांसदों पर हत्या, रेप और लूट के मामलों में आरोप हैं। इन आपराधिक मुकदमों के बाद भी ये नेता भारत की संसद का हिस्सा हैं, यह विडंबना ही है। अंत में, यही कहूंगा कि विपक्षी नेताओं ने इन विधेयकों को लोकतंत्र विरोधी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया है, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि जनता तय करे, पीएम...सीएम या मंत्री को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। हाल फिलहाल, देखना यह होगा कि संयुक्त संसदीय समिति इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें संसद को कब, क्या और कैसे सौंपती है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि जेपीसी(संयुक्त संसदीय समिति) एक महत्वपूर्ण संसदीय उपकरण है जिसका उपयोग संसद द्वारा किसी विशेष मामले या विधेयक की गहन जांच और विश्लेषण के लिए किया जाता है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

चुनाव आयोग की कमजोरियां सामने आ गयी

राजेश कुमार पासी

राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार हमले कर रहे हैं कि उसने भाजपा से मिलकर चुनाव चोरी किया है । चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र रूप से काम करती है ।इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र रूप से काम करती है । इस समय विपक्ष चुनाव आयोग पर हमले कर रहा है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू कर देता है जब कोई फैसला उसके एजेंडे के खिलाफ आ जाता है । इस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरा विपक्ष उनके एजेंडे पर चल रहा है । कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए संवैधानिक व्यवस्थायों का अपने हितों में इस्तेमाल किया है इसलिए राहुल गांधी को लगता है कि मोदी सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रही है । देखा जाए तो ये सच भी है कि जो भी दल सत्ता में होता है वो संवैधानिक संस्थाओं पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है । सवाल यह है कि अगर भाजपा ऐसा कर भी रही है तो उसके खिलाफ अभियान तब चलाया जाना चाहिए जब विपक्ष के हाथ में ठोस सबूत हों लेकिन हो यह रहा है कि विपक्ष व्यवस्था की विसंगतियों को इंगित करके भाजपा पर हमला कर रहा है । अजीब बात यह है कि यह विसंगतियां खुद कांग्रेस ने ही पैदा की हैं या कांग्रेस के समय से चली आ रही हैं । राहुल गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों को मीडिया के सामने रखा और कहा कि इन विसंगतियों के सहारे भाजपा ने चुनाव चोरी किया है ।

चुनाव आयोग ने अपनी बात रखने के लिए एक बड़ी प्रेस कांफ्रेंस की और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए । चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है इसलिए भाजपा उसका बचाव नहीं कर सकती । चुनाव आयोग को यह बात समझ आ गई है कि उसे अपनी छवि बचाने के लिए देश को अपना पक्ष बताना पड़ेगा । मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़ी साफगोई से अपनी बात मीडिया के सामने रखी लेकिन अंजाने में ही वो चुनाव आयोग की कमजोरियां देश के सामने रख गए । अजीब बात यह है कि उन्होंने जिन कमजोरियों को बड़ी सहजता के साथ मीडिया में रखा, उससे लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी कमजोरियों का अहसास ही नहीं है । सच तो यह है कि राहुल गांधी इन्हीं कमजोरियों को सामने लाकर चुनाव चोरी का विमर्श चलाने की कोशिश कर रहे हैं । बेशक ज्ञानेश कुमार ने मीडिया के सवालों के जवाब अच्छी तरह दिए लेकिन फिर भी कुछ सवाल बाकी रह गए । चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस में एक साथ पांच सवाल लिए जा रहे थे और फिर उनके जवाब एक साथ दिए जा रहे थे । मैंने जीवन में ऐसा पहली बार देखा है कि पांच सवाल एक साथ लेकर जवाब दिए जाएं । पता ही नहीं चल रहा था कि वो किसके सवाल का जवाब दे रहे हैं । इसके कारण कई सवालों के जवाब अस्पष्ट रह गए हालांकि उन्होंने किसी भी सवाल से बचने की कोशिश नहीं की ।

चुनाव आयोग को मोदी की तरह विपक्ष की तरफ से बेपरवाह होकर काम करना चाहिए लेकिन अपनी कमियों से दूर नहीं भागना चाहिए।

नेमरा गाँव: सबक या सवाल?

अशोक कुमार झा

क्या विकास सिर्फ़ 'वीआईपी गाँवों' का अधिकार है?

झारखंड की राजनीति और सत्ता का एक अहम केंद्र रहा है नेमरा गाँव। यही वह जगह है जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का गढ़ कहा जाता है। यहीं से देश को 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन जैसे बड़े नेता मिले और यहीं तीन बार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक गाँव स्थित है। लेकिन हाल ही में जो दृश्य नेमरा गाँव में देखने को मिला, उसने पूरे राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहस को जन्म दे दिया है।

सिर्फ़ 10 दिनों में गाँव की सूरत बदल दी गई। धूल-कीचड़ से जूझता नेमरा अचानक सड़क, बिजली, रोशनी और वाई-फाई युक्त गाँव बन गया। अफ़सर रात-दिन लगे, ठेकेदारों ने रिकॉर्ड स्पीड दिखाई, फंड तुरंत उपलब्ध हो गया और सरकारी तंत्र ने यह साबित कर दिया कि अगर सरकार ठान ले तो विकास रातों-रात भी संभव है।

लेकिन इसके साथ ही यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है —

क्या विकास सिर्फ़ नेमरा जैसे 'विशेष गाँवों' के लिए ही सुरक्षित है?

क्या बाकी गाँवों को सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट के लिए वर्षों की प्रतीक्षा करनी होगी?

क्या लोकतंत्र में आम जनता का अधिकार भी 'पद' और 'पदवी' पर टिका हुआ है?

नेमरा की रफ़्तार — बाकी गाँवों का इंतज़ार

नेमरा गाँव में अचानक सब कुछ बदल गया। जिन योजनाओं के लिए सामान्य परिस्थितियों में विभाग वर्षों की फाइलबाज़ी और टेंडर प्रक्रिया में उलझा रहता है, वह यहाँ हफ़्ते भर में पूरी हो गई। अफ़सरों ने रातभर काम किया, ठेकेदारों ने मशीनें झोंक दीं, बिजली के खंभे खड़े हो गए, सड़कें पक्की हो गईं और गाँव जगमगाने लगा।

लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था —

अगर नेमरा में 10 दिन में यह सब संभव है तो बाकी गाँवों में क्यों नहीं?

क्या बाकी झारखंडी गाँव कमतर हैं?

झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों गाँव हैं जहाँ आज भी सड़क नहीं पहुँची, जहाँ बच्चे टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करते हैं, जहाँ गर्भवती महिलाएँ कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर अस्पताल तक पहुँचाई जाती हैं। उन गाँवों में भी तो इंसान रहते हैं, वोट देते हैं, कर चुकाते हैं, फिर उन्हें यह सुविधाएँ क्यों नहीं मिलतीं?

VIP बनाम आम गाँव

हिंदुस्तान में यह समस्या नई नहीं है। जिस नेता या अफ़सर का गाँव होता है, वहाँ विकास का पहिया तेज़ घूमता है। वहीं आसपास के गाँवों की हालत जस की तस रहती है।

बिहार के कई जिलों में देखा गया कि नेताओं के पैतृक गाँवों को 'आदर्श गाँव' बना दिया गया, जबकि बगल के गाँव गड्ढों और अंधेरे में डूबे रहे।

उत्तर प्रदेश में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के गाँवों में हवाई चप्पल पहनने वाला भी पक्की सड़क पर चलता है, लेकिन ठीक पास के गाँव में कीचड़ और धूल से लोग ग्रस्त रहते हैं।

झारखंड में तो यह और भी स्पष्ट है। रांची से कुछ ही किलोमीटर दूर बसे गाँवों तक सड़क और बिजली नहीं पहुँची, लेकिन नेमरा जैसे गाँव 10 दिनों में हाईटेक बन जाते हैं।

यानी सवाल साफ़ है —

क्या विकास का हक़ सिर्फ़ VIP गाँवों का है?

क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ़ 'नेताओं का गाँव पहले' होता है?

क्या बाकी जनता 'कम झारखंडी' है?

झारखंड की आत्मा उसके गाँवों में बसती है। यहाँ की पहचान ही जल, जंगल और ज़मीन से है। लेकिन आज भी 40% से अधिक गाँव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

हज़ारों गाँवों में सड़क नहीं है।

बिजली कागज़ों पर पहुँची है, हकीकत में पोल और तार टूटे पड़े हैं।

पीने का पानी हैंडपंप पर निर्भर है।

इंटरनेट और डिजिटल सुविधा तो दूर की बात है।

नेमरा ने साबित कर दिया कि यदि सरकार चाह ले तो एक गाँव को 10 दिन में वाई-फाई युक्त बना सकती है। लेकिन यही सुविधा जब बाकी गाँव माँगते हैं तो कहा जाता है — "फंड की कमी है, प्रक्रिया लंबी है और योजना पेंडिंग है।"

तो क्या बाकी जनता झारखंडी नहीं? क्या उनके वोट की कीमत कम है? क्या उनका जन्म VIP घरानों में न होना ही उनकी सबसे बड़ी कमी है?

असली समस्या — नियत और प्राथमिकता

झारखंड में पैसे की कमी नहीं है। खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य में हर साल अरबों का राजस्व आता है। केंद्र सरकार से भी योजनाओं के लिए भारी-भरकम फंड मिलता है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि:

योजनाएँ कागज़ों में फँस जाती हैं।

टेंडर प्रक्रिया सालों चलती रहती है।

ठेकेदार और अफ़सर पैसे का खेल खेलते रहते हैं।

गाँववाले इंतज़ार करते रहते हैं।

यानी मतलब पूरी तरह से साफ़ है, समस्या पैसों की नहीं, नियत और प्राथमिकता की है।

नेमरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ सरकार की प्राथमिकता बनी, अफ़सरों ने काम किया और 10 दिनों में चमत्कार हो गया। तो सवाल यह है कि बाकी गाँवों के लिए सरकार कब अपनी प्राथमिकता बदलेगी?

राजनीति बनाम जनता का हक़

हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में विकास अब भी राजनीतिक समीकरणों और 'पद' पर निर्भर करता है। नेमरा में जो हुआ, वह जनता के हक़ से ज़्यादा राजनीतिक संदेश था।

एक तरफ़ अफ़सर और मंत्री साबित करना चाहते थे कि वे "नेताओं का गाँव" तुरंत बदल सकते हैं।

दूसरी तरफ़ इसका राजनीतिक लाभ भी साफ़ दिखता है — जनता को यह दिखाना कि "देखिए, हम काम कर रहे हैं।"

लेकिन आज जनता पूछ रही है —

क्या विकास सिर्फ़ चुनावी पोस्टर का हिस्सा रहेगा?

क्या आम आदमी को सड़क और रोशनी सिर्फ़ भाषणों में मिलेगी?

पूरे झारखंड को "नेमरा" क्यों नहीं?

झारखंड के 32,000 से अधिक गाँवों में अगर एक-एक नेमरा जैसी कहानी लिखी जाए, तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है।

सड़क हर गाँव तक पहुँचे।

बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो।

इंटरनेट से बच्चा पढ़ सके, किसान मंडी से जुड़ सके।

अस्पताल की सुविधा हर पंचायत में हो।

स्कूल सिर्फ़ भवन नहीं, पढ़ाई देने वाले हों।

यह सब संभव है। नेमरा ने साबित कर दिया कि सरकार चाह ले तो हफ्ते-दस दिन में भी बदलाव संभव है। बस ज़रूरत है राजनीतिक इच्छाशक्ति की।

जनता की उम्मीद

झारखंड के लोग अब यही पूछ रहे हैं —

क्या हमें भी VIP गाँव बनने के लिए किसी "दिशोम गुरु" की ज़रूरत है?

क्या हमारे अधिकार भी किसी नेता की पैतृक ज़मीन से जुड़कर ही मिलेंगे?

क्या लोकतंत्र का मतलब यही है कि आम जनता का विकास 'कागज़ों' पर हो और असली काम सिर्फ़ VIP इलाक़ों में?

जनता की उम्मीद साफ़ है —

अगर नेमरा में संभव है, तो बाकी गाँवों में भी होना चाहिए। अगर वहाँ 10 दिनों में सड़क और वाई-फाई आ सकता है, तो बाकी गाँवों में सालों-साल क्यों लगते हैं?

नेमरा गाँव ने पूरे राज्य को एक आईना दिखाया है। यह साबित कर दिया है कि जहाँ सरकार चाहती है, वहाँ विकास संभव है। लेकिन यह भी उजागर कर दिया है कि बाकी गाँवों की उपेक्षा केवल सरकार की प्राथमिकता और राजनीतिक खेल का हिस्सा है।

अब सवाल जनता का है —

क्या झारखंड सरकार पूरे राज्य को "नेमरा" बनाएगी या फिर विकास सिर्फ़ नेताओं के गाँव तक सीमित रहेगा?

क्या लोकतंत्र में हर नागरिक बराबर है या फिर गाँव भी 'VIP बनाम आम' में बाँटे जाएँगे?

झारखंड की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। नेमरा ने उम्मीद भी जगाई है और सवाल भी खड़े किए हैं। अब सरकार को तय करना होगा कि वह इस चुनौती को स्वीकार करती है या फिर जनता को फिर से इंतज़ार के अंधेरे में छोड़ देती है।

खुर्दा रोड-पलासा खंड पर आधुनिकीकरण कार्य शुरू; 24 सितंबर तक ट्रेन सेवाओं में बदलाव

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत खुर्दा रोड-पलासा खंड पर सुरक्षा संबंधी आधुनिकीकरण कार्य चल रहा है। इस संबंध में ट्रेनों के समय-सारिणी में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। 24 सितंबर तक तीन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और चार के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।ट्रेन संख्या 68419 भुवनेश्वर-पलासा मेमू पैसेंजर शनिवार, रविवार, सोमवार और बुधवार को रद्द रहेगी। पलासा-भुवनेश्वर मेमू पैसेंजर (ट्रेन संख्या 68420) अगले रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को रद्द कर दी गई है। भुवनेश्वर-बरहरापुर-भुवनेश्वर मेमू पैसेंजर शनिवार, रविवार, सोमवार और बुधवार को रद्द रहेगी। कटक-पलासा मेमू (68445) शनिवार, रविवार, सोमवार और बुधवार को पलासा के बजाय इच्छापुरम तक चलेगी। गुनुपुर-कटक मेमू (68434) रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को गुनुपुर के बजाय इच्छापुरम से चलेगी। बरहामपुर-विशाखापत्तनम पैसेंजर (58531) बुधवार, रविवार, सोमवार और शनिवार को बरहामपुर के बजाय पलासा से चलेगी। इसके अलावा, विशाखापत्तनम-बरमहपुर पैसेंजर (58532) मंगलवार, शनिवार, रविवार और शुक्रवार को बरमहपुर के बजाय पलासा तक चलेगी।

50 साल बाद भी हिन्दी फिल्मों की सबसे बड़ी सुपर-डुपर हिंट फिल्म शोले - यादों के संस्मरण

हिंदी सिनेमा इतिहास में शोले जैसी फिल्म के हर एक किरदार आज भी मानस पटल पर अंकित है।

स्वतंत्र लेखक - हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

'हेट एण्ड टेल सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहीं जाना हो या कोई काम करना हो कुछ करना हो तो वह टांस होना भी फिल्म शोले का अलग ही अंदाज ही था। फिल्म की शुरुआत में जो दृश्य फिल्माए गए वह उस जमाने की सबसे शानदार चलचित्रों में था। भारतीय हिन्दी सिनेमा की नींव का पत्थर इस फिल्म को कहे तो कोई ग़लती नही होगी। फिल्म के लेखक सलीम जावेद की इस जोड़ी ने हर एक किरदार को छेनी हथौड़ी से तराश कर जीवित किया था। जैसे बसंती (हेमा-मालिनी) की बात करने की हर एक स्टाईल बहुत निराली थी। और

उस गांव की तांगेवाली की घोड़ी धन्नो भी अलग-अलग रंग में दिखी। रामगढ़ की रहने वाली बसंती की बात तो सौ बात की सौ बात ही थी। जब रेलगाड़ी से रेलवे स्टेशन पर दो जवान लड़के शहर से आते हैं वह कहते हैं कि हमें रामगढ़ जाना है....। अच्छा अच्छा पर वहां कहा जायेंगे ? ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है।

बाबू जी आप सोच रहे होंगे की बसंती लड़की होकर तांगा चलातीं है...।

अरे जब धन्नो घोड़ी होकर तांगा चला सकती है तो हम क्यों नहीं चला सकते हैं। यह इठलाते हुए संवाद और जय और वीरू का किरदार निभाते अमिताभ व धर्मेंद्र अपने आप में अलग ही थें। शोले फिल्म में हर एक छोटे-से छोटे किरदार प्रभावी व सटिक रहे ।15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई फिल्म को आज 50 साल हो चुके हैं पर इतने वर्षों बाद भी हिन्दी फिल्मों की रीड की हड्डी है फिल्म शोले।

हर एक किरदार के अपने अलग-अलग अंदाज देखते ही बनता था जैसे कि

ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली में काम करने वाले नौकर रामलाल हो या फिर मौलवी बने ए के हंगल जी हो वही ठाकुर साहब की सबसे छोटी बहू जया बच्चन पहली झलक में बहुत सीधी साधी सी विधवा बहूं के किरदार में अच्छा प्रभाव छोड़ कर गई ।वहीं आहमत मियां का किरदार में सचिन ने थोड़े समय के लिए अपने आप के अभियान को पूर्ण रूप से न्याय किया था। इस फिल्म के चार प्रमुख स्तंभ थे वहीं दो आंतरिक महत्वपूर्ण सारथी भी थे ।जय वीरू ठाकुर बलदेव सिंह डाकु गब्बर सिंग बसंती व ठाकुर साहब की विधवा बहू इन्हीं के आसपास फ़िल्मी कैमरा जरुर घूमा पर जब कोई मनोरंजन व्यंग्य कमेड़ी की बात होगी तो असरानी जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर से शुद्ध मनोरंजन किया वहीं हरिराम नाई की चुगली ने दशकों को चंद मिनटों के लिए गुदगुदाया। इस फिल्म शोले में धमेंद्र ,अमिताभ, संजीव कुमार ,अमजद खान, हेमा-मालिनी, जय बच्चन का अभियान इतने सालों बाद भी सिनेप्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। नई पीढ़ी भी अगर शोले फिल्म को देखतीं हैं तो वह बीच में उठकर कहीं जा आ नहीं सकती है ।वह वहीं ठहर सी जाती है इस फिल्म के संवादों ने दशकों को बंधे रखा था ।जैसे बेलापुर जाने के लिए बसंती व धन्नो की बातचीत या मौसी जी और जय का संवाद हमारा लड़का ऐसे तो पैसे बहुत कमाता है पर शाम जुआं खेलने बैठ जाता है और भी कई प्रसंग दशकों को बंधे रखतें थें। गांव के देसी परिवेश में बातचीत का अनोखा रंग फ़िल्मी दृश्य बहुत जोरदार बने थे ।इस फिल्म का एक एक सीन फिल्म का मजबूत हिस्सा था। जिसके बल पर सुपर-डुपर हिंट नहीं बल्कि लाखों करोड़ों चाहने वालों के दिलों में आज 49 साल बाद भी शोले जिंदा है तभी तो आज भी शोले जैसी हिंदी फिल्म अपने इतिहास के स्वर्णिम सफ़र पर है ....। इतने वर्षों बाद भी चाहने वालों के दिलों में आज भी राज कर रही है यह फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक जे पी सिप्पी व रमेश सिप्पी जी ने बनाई थी जिसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी था इस फिल्म को बनाने में ।इस फिल्म में जब डाकु गांव में आते थे जब दर्शक भी बहुत डर से जाते थे ।वहीं डाकु कालिया का सीन दो मुठ्ठी ज्वार लायें हो ।वहीं फिर डायलॉग ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाईं है / ठाकुर बोलते हैं मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी हैं ।वहीं डाकु गब्बर सिंह का डायलॉग कितने आदमी थे सरकार दो आदमी थे / गब्बर .... सुअर के बच्चों वह दो थे तुम तीन फिर भी खाली हाथ आ गये.....। तम्बाकू की पोटली से ठेठ देसी अंदाज में अमजद खान साहब का अभियान ने डर व खोफ की इबादत अपने अभिनय से लिखी उन्होंने उस अभिनय को अमर कर दिया ।तभी तो पचास पचास कोस दूरी पर जब कोई बच्चा रोता है तो मां बोलती है सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जायेगा। इसी बीच बंदूक की गोली भरते भरते तीनों डाकुओं की हंसी गब्बर का संवाद ने ज़िन्दगी व मौत के बीच तड़का लगा दिया। डाकु गब्बर सिंह का डायलॉग तेरा क्या होगा कालिया ... कालिया मेने आप का नमक खाया है, अब गोली खा ...। फिल्म शोले में होली कब हैं आमजन का डायलॉग बना हुआ है इतने वर्षों बाद भी उसी पर फिल्माया हिट गाना होली के दिन दिल मिल जातें हैं रंगों में रंग मिल जातें हैं । भारतीय परिधानों का रंगीन व सतरंगी आसमान में जब इस फिल्म को बनाया गया तब और उसके बाद इस गीत की धूम वर्तमान में भी उसी उंमगता के साथ बनी हुई है। इसी होली की मस्ती के बीच रामगढ़ में ड़ाकू आते हैं और ठाकुर साहब बन्दूक नहीं उठा पाते हैं उसके बाद गब्बर का संवाद .... ठाकुर इन्हें लायें थें रामगढ़ में गब्बर से रक्षा के लिए ? गब्बर के खोफ से एक आदमी बचा सकता वह है खुद गब्बर ।धन्नो का तांगा से बसंती की बुद्धि कौशल के जरिए गब्बर से लड़ाई में गांव वालों की जीत होती है ।

वहीं बहुचर्चित डायलॉग लोहा गरम है मर दो हाथोडा और आर डी बर्मन दा का गीत व संगीत आवाज भी उनकी महबूबा हो महबूबा गुलशन में गुल खिलाते हैं या फिर इस फिल्म का एक और गाना कोई हसीना जब रुठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। इसी फिल्म शोले का सबसे लोकप्रिय गीत मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जय की मौत पर जब यह गाना बचता है तो गमगीन माहौल हो जाता है। ऐसे तो इस फिल्म में गाने कम थे मगर जो भी थे वह रजत पटल पर रखे हुए कर्ण प्रिय थे । वहीं धमेंद्र का वह यादगार सीन जिसमें पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी के लिए प्रस्ताव निराले अंदाज में फिल्माया गया था ।जिस में किरदार में रहे कर धर्मेन्द्र वीरू ने एक अलग छाप छोड़ी। वहीं ए क हंगल साहब का एक छोटा सा डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है भाई....। कौन यह बोझ नहीं उठा सकता ...। सबसे बड़ा बोझ बेटे का जनाजा बाप के कन्धे पर उठना होता है। वहीं सलीम जावेद की लेखनी में असली किरदार सूरमा भोपाली का अलग ही था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इस ऐतिहासिक फिल्म को चित्र पट जगत की सबसे बड़ी व सुपर-डुपर हिट मानी जाती है। फिल्म शोले आज इसी लिए हिन्दी सिनेमा जगत के बेमिसाल इतिहास के स्वर्णिम सफ़र पर है ...। क्योंकि लोकप्रियता में इस का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है ।50 सालो की लम्बी फिल्मी यात्रा आज भी यादगार पलों में बनी हुई है ।इस फिल्म ने कई पीढीयों के गुज़र जाने के बाद भी आज जब कभी या फिल्म आतीं हैं टेलीविजन में आतीं हैं तो दर्शक स्थिर हो जाते है। हर एक चीज में यह फिल्म जनमानस के पटल पर रेखांकित करती है ।संवाद डायलॉग गीत संगीत या शोले के कोई भी किरदार हर एक चीज मन-मस्तिष्क पर बनीं हुईं हैं जो चिरस्मरणीय है। शोले जैसी फिल्म फिर कभी भी नहीं बन सकतीं यह फिल्मी दुनिया के लिए अजुबा ही है। तभी तो इतने वर्षों बाद भी इस फिल्म के बारे में लिखते लिखते बहुत कुछ पहेलू छुट गये पर जो हम दशकों में फिल्मों के प्रति समर्पित जिंदादिल इंसान के ज़हन में जो भाव थे वह सब आप के लिए लिखें है क्योंकि शोले जैसी हिंदी फिल्म सिनेमा इतिहास के स्वर्णिम सफ़र पर है। इसके हर एक किरदार मानस पटल पर आज भी अंकित है।

ओडिशा में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर शहरी विकास मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र ने फिर दिखाया सपना

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : ओडिशा में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर राज्य सरकार ने फिर दिखाया सपना। केंद्र सरकार के सहयोग और सलाह से मेट्रो का निर्माण होगा। शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने कहा कि केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट आने के बाद मेट्रो परियोजना का निर्माण होगा। बीजद ने कहा कि मेट्रो को लेकर मंत्री के बयानों में एकरूपता नहीं है। वहीं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मेट्रो के मुद्दे पर स्पष्टता लाने की मांग की है।

मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर भाजपा सरकार असमंजस में है। कभी हाँ तो कभी ना। हर घंटे बयान और फैसले बदल रहे हैं। राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर केंद्र से सहयोग मांगा है। शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और सलाह से मेट्रो का काम आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। मंत्री के अनुसार, मेट्रो परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति विभिन्न स्थानों पर जाकर सर्वेक्षण करेगी। रिपोर्ट आने के बाद केंद्र से मदद मांगी जाएगी। समिति इस बारे में रिपोर्ट देगी कि मेट्रो को कैसे संभव बनाया जाएगा। उसके अनुसार, राज्य द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, केंद्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और परियोजना की लागत कितनी होगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने स्वीकार किया कि मेट्रो परियोजना के लिए पहले से ही एक निश्चित राशि आवंटित है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भी केंद्र सरकार के साथ इस पर चर्चा करेंगे।

राजधानी में मेट्रो चलेगी या नहीं, इस दुविधा को लेकर सरकार दो विपक्षों से घिरी हुई है। बीजद नेता अशोक पांडा ने कहा कि यह तय नहीं हुआ है कि भाजपा उस मेट्रो परियोजना को चलाएगी या नहीं, जिसका शिलान्यास बीजद सरकार के दौरान किया गया था। 14 महीने पुरानी भाजपा सरकार के दौरान मेट्रो परियोजना अनिश्चितता में चली गई है। मेट्रो परियोजना के संबंध में शहरी विकास, निर्माण और परिवहन मंत्री के बयान में एकरूपता नहीं है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1 अप्रैल, 2023 को मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी थी। 1 जनवरी, 2024 को नवीन पटनायक ने त्रिशूलिया में मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखी। काम भी शुरू हो गया है। पहले चरण में भुवनेश्वर हवाई अड्डे से त्रिशूलिया तक मेट्रो का निर्माण होना था। इस परियोजना पर कुल 6,255 करोड़ रुपये खर्च होने थे। हालाँकि, बीजद का कहना है कि मेट्रो का टेंडर रद्द होने के बाद लगभग 500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। इसी तरह, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति ने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य की जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि ओडिशा में मेट्रो बनेगी या नहीं।

नवीन सरकार के दौरान शुरू हुई इस मेट्रो परियोजना को 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालाँकि, ओडिशा में सरकार बदलने के बाद, मेट्रो परियोजना बनेगी या नहीं, यह अनिश्चितता में पड़ गया है। और इसे लेकर राज्य की राजनीति में सियासत शुरू हो गई है।

रांची में तीन सीओ, दो सीआई, दो कर्मचारी के ऊपर जमीन फर्जीवाड़े को लेकर एफआईआर

समुचा झारखंड भ्रष्ट भू - राजस्व अधिकारी एवं जमीन दलालों के चंगुल में कर रहा त्राहि त्राहि

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, आदिवासी मूल निवासियों के हित के लिये सन 2000मे बिहार से पृथक हुआ झारखंड अब जमीन फर्जीवाड़े का प्रदेश के रूप में उभरता हुआ राज्य बनने जा रहा है । अगर एक 83 वर्षीया निसंतान महिला के साथ ऐसा कुछ हो तो मामले की भयावहता कितनी दर्दनाक होगी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है । जहां फर्जी डीड , फर्जी वंशावली ,फर्जी पंजी -2, समेत शपथ पत्र बनाना आम बात हो गयी है ।अब एसआईटी की अनुशंसा पर एक मामला रांची में पुनः दर्ज की गयी है । ऐसे मामले केवल रांची नहीं अपितु झारखंड के हर अंचल में विद्यमान है, दरकार है निष्पक्ष व ईमानदार एजेंसी की । अधिकारी, कर्मचारी एवं दलालों की मिली भगत के कारण खासकर कमजोर एवं निरीह लोगों को इसके शिकार हो रहे हैं ।

ऐसे ही कुछ भ्रष्टाचार के आरोप में अब राजधानी रांची के तीन सीओ, दो सीआइ एवं दो राजस्वकर्मियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीद बिक्री करने का आरोप लगे है ,जिसपर प्राथमिकी तक दर्ज हुई है । जांच के बाद सीआईडी एसआईटी की अनुशंसा पर एफ आई आर को दर्ज कराया गया है । जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा के मामले में रांची के चुटिया थाने में तीन अंचलाधिकारी , दो अंचल निरीक्षक एवं दो राजस्वकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है ।जिनके विरुद्ध ये कांड दर्ज की गई है, उनमें अंचलाधिकारी रवींद्र कुमार, अरविंद कुमार ओझा व सुमन कुमार सौरभ के अलावा अंचल निरीक्षक कमलकांत वर्मा, अनिल कुमार गुप्ता तथा राजस्व कर्मचारी सुनील मिंज व मनोरथ भगत शामिल हैं।

अन्य आरोपितों में चुटिया के महादेव मंडा निवासी रवि गोप, नवनीत महतो, आयुष महतो, रवि गोप की पत्नी लक्ष्मी देवी, नवनीत महतो की पत्नी बीना देवी व अन्य अज्ञात सरकारी कर्मी शामिल हैं।

इन सभी आरोपितों पर फर्जी डीड, फर्जी वंशावली, फर्जी पंजी-2, फर्जी शपथ पत्र तैयार करने एवं सरकारी पद का दुरुपयोग कर रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप है।

आरोप है कि जालसाजी कर एक 83 वर्षीय निःसंतान महिला अस्तोरन देवी को बहाला-फुसलाकर मोहरा बनाकर आपराधिक साजिश के तहत सामूहिक रूप से जमीन का फर्जीवाड़ा किया गया है।

रांची के चुटिया थाने में दर्ज यह प्राथमिकी सीआइडी के संगठित अपराध के आइजी सुदर्शन प्रसाद मंडल के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) की अनुशंसा पर दर्ज की गई है।

आइडी की एसआइटी के पास गीता ज्ञानी नामक महिला ने 28 अगस्त 2024 को लिखित शिकायत की थी। उन्होंने उपरोक्त सभी आरोपितों पर फर्जीवाड़ा कर कृष्णापुरी चुटिया की उक्त विवादित जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया था।एसआइटी ने सभी आरोपितों के बयान लिए, कागजात की जांच की और उसके बाद ही इस मामले में रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच व कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसी अनुशंसा पर प्राथमिकी दर्ज हुई है

डिप्टी कमिश्नर द्वारा अवैध रूप से निजी जानकारी एकत्र करने वाले व्यक्तियों को चेतावनी

लोगों से सतर्क रहने और अनधिकृत व्यक्तियों के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करने की अपीलभी

अमृतसर, 21 अगस्त (साहिल बेरी)

सरकार को कुछ निजी ऑपरेटरों द्वारा कथित रूप से गैर-कानूनी तरीके से स्थानीय निवासियों की निजी जानकारी एकत्र करने संबंधी विश्वसनीय रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

इस संबंध में चेतावनी देते हुए आज अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP एक्ट) के तहत सहमति के बिना निजी जानकारी एकत्र करना या उसका उपयोग करना दंडनीय अपराध है। इस कारण स्थानीय पुलिस को ऐसे गैर-कानूनी कार्यों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने बताया कि यह भी संज्ञान में आया है कि अपनी निजी जानकारी साझा करने वाले कई लोग पैसों की हेरफेर, फोन नंबर और ओटीपी के दुरुपयोग जैसे मामलों में धोखाधड़ी और बैंकिंग फ्रॉड का शिकार हुए हैं।

इसलिए उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि वे अपनी निजी जानकारी किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंसी के साथ साझा न करें, क्योंकि उनकी जानकारी का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग किया जा सकता है। नागरिकों को सतर्क रहने और ऐसी किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि की तुरंत अधिकारियों को सूचना देने की सलाह दी जाती है।

इस संबंध में कोई भी शिकायत या सूचना ईमेल आईडी dproamritsar3@gmail.com पर भेजी जा सकती है।

भ्रष्टाचार के बारूदी ढेर पर जमीन का खेल, लिया बारह हजार पहुंचा जेल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची, झारखंड में जमीन संबंधी धांधली व रिश्वतखोरी का मामला दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है । इस क्रम में आज गढ़वा जिले में एक राजस्व उप निरीक्षक (भू राजस्व विभाग के कर्मचारी) को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की पलामू प्रमंडलीय टीम ने यह कार्रवाई की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिसुनजय राम ने रिश्वत मांग संबंधी एक मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पास 2011 में खरीदी गई 7.5 डिसमिल जमीन का केवाला रसीद है। इस जमीन को ऑनलाइन करने के लिए रमकंडा अंचल के राजस्व उप निरीक्षक अरुण कुमार यादव ने 12 हजार रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद एसीबी पलामू ने मामले की जांच की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना बनाई गई। गुरुवार को दंडाधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। 31 वर्षीय आरोपी अरुण कुमार यादव को शिकायतकर्ता से 12 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के सासंग गांव का रहने वाला है। वर्तमान में वह रमकंडा अंचल में हल्का नंबर 9 का राजस्व उप निरीक्षक था ।

बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद

रात के अंधेरे में साजिश के तहत वर्तमान प्रधान पर जान लेवा हमले की कोशिश, जान से मारने की नियत से वर्तमान प्रधान के घर में घुसा युवक, गांव में मुख्य मार्ग पर लगे कैमरे तोड़ अन्य साथियों के साथ प्रधान के घर में घुसा युवक, आहट सुनकर जाग रहे परिवार ने युवक को धर दबोचा,बनाया बंधक, अन्य साथी मौका देख हुए फरार, घटना से पहले घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हुए युवक का ऑडियो भी हुआ वायरल, पुलिस को दी सूचना घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को मय तमंचे के साथ लिया हिरासत में, उघैती पुलिस की उदासीनता के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद, पूरा मामला थाना उघैती क्षेत्र के रघुनाथपुर पीपरी गांव का बताया जा रहा है।

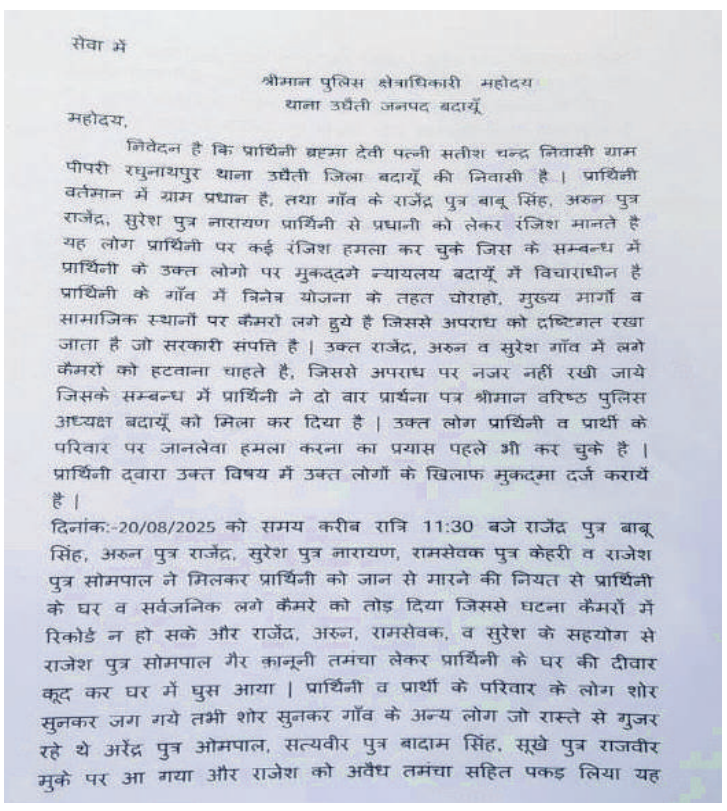

सेवा में

श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय
थाना उघैती जनपद बदायूँ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिनी ब्रहमा देवी पत्नी सतीश चन्द्र निवासी ग्राम पीपरी रघुनाथपुर थाना उघैती जिला बदायूँ की निवासी है। प्रार्थिनी वर्तमान में ग्राम प्रधान है, तथा गॉव के राजेंद्र पुत्र बाबू सिंह, अरुन पुत्र राजेंद्र, सुरेश पुत्र नारायण प्रार्थिनी से प्रधानी को लेकर रंजिश मानते है यह लोग प्रार्थिनी पर कई रंजिश हमला कर चुके जिस के सम्बन्ध में प्रार्थिनी के उक्त लोगो पर मुकद्दमे न्यायलय बदायूँ में विचाराधीन है प्रार्थिनी के गॉव में त्रिनेत्र योजना के तहत चोराहो, मुख्य मार्गो व सामाजिक स्थानों पर कैमरो लगे हुये है जिससे अपराध को दृष्टिगत रखा जाता है जो सरकारी संपत्ति है। उक्त राजेंद्र, अरुन व सुरेश गॉव में लगे कैमरों को हटवाना चाहते है, जिससे अपराध पर नजर नहीं रखी जाये जिसके सम्बन्ध में प्रार्थिनी ने दो बार प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष बदायूँ को मिला कर दिया है। उक्त लोग प्रार्थिनी व प्रार्थी के परिवार पर जानलेवा हमला करना का प्रयास पहले भी कर चुके है। प्रार्थिनी द्वारा उक्त विषय में उक्त लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करायें है।

दिनांकः-20/08/2025 को समय करीब रात्रि 11:30 बजे राजेंद्र पुत्र बाबू सिंह, अरुन पुत्र राजेंद्र, सुरेश पुत्र नारायण, रामसेवक पुत्र केहरी व राजेश पुत्र सोमपाल ने मिलकर प्रार्थिनी को जान से मारने की नियत से प्रार्थिनी के घर व सर्वजनिक लगे कैमरे को तोड़ दिया जिससे घटना कैमरों में रिकोर्ड न हो सके और राजेंद्र, अरुन, रामसेवक, व सुरेश के सहयोग से राजेश पुत्र सोमपाल गैर कानूनी तमंचा लेकर प्रार्थिनी के घर की दीवार कूद कर घर में घुस आया। प्रार्थिनी व प्रार्थी के परिवार के लोग शोर सुनकर जग गये तभी शोर सुनकर गॉव के अन्य लोग जो रास्ते से गुजर रहे थे अरेंद्र पुत्र ओमपाल, सत्यवीर पुत्र बादाम सिंह, सूखे पुत्र राजवीर मुके पर आ गया और राजेश को अवैध तमंचा सहित पकड़ लिया यह

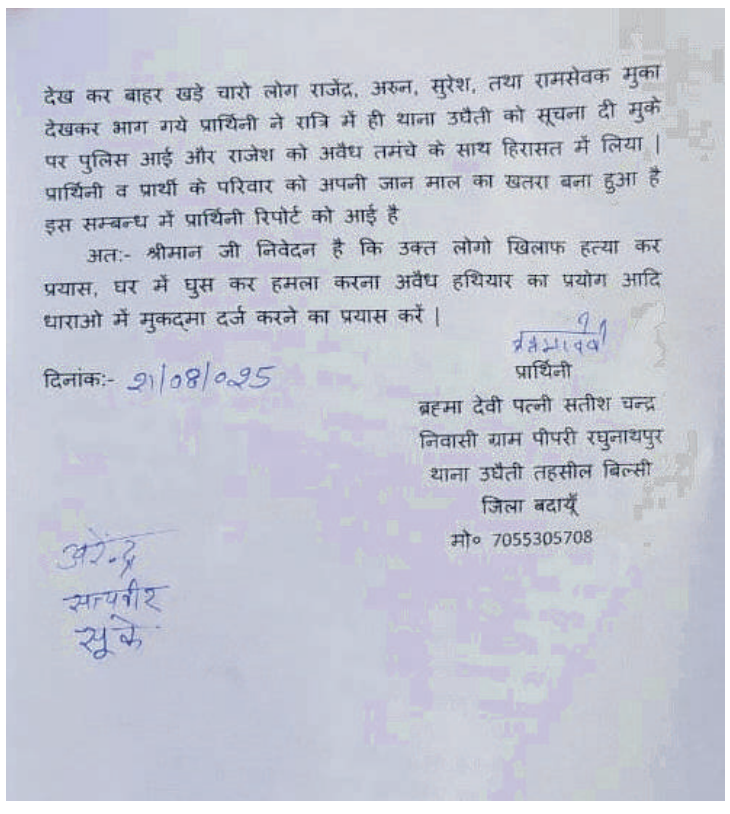

देख कर बाहर खड़े चारो लोग राजेंद्र, अरुन, सुरेश, तथा रामसेवक मुका देखकर भाग गये प्रार्थिनी ने रात्रि में ही थाना उघैती को सूचना दी मुके पर पुलिस आई और राजेश को अवैध तमंचे के साथ हिरासत में लिया। प्रार्थिनी व प्रार्थी के परिवार को अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है इस सम्बन्ध में प्रार्थिनी रिपोर्ट को आई है

अतः- श्रीमान जी निवेदन है कि उक्त लोगो खिलाफ हत्या कर प्रयास, घर में घुस कर हमला करना अवैध हथियार का प्रयोग आदि धाराओ में मुकदमा दर्ज करने का प्रयास करें।

दिनांकः- 21/08/025

प्रार्थिनी
ब्रहमा देवी पत्नी सतीश चन्द्र
निवासी ग्राम पीपरी रघुनाथपुर
थाना उघैती तहसील बिल्सी
जिला बदायूँ
मो० 7055305708

1500 म्यूल बैंक एकाउंट की हुई पहचान, सात अन्तराज्य साइबर अपराधी सीआईडी के हत्थे चढ़े

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने साइबर क्राइम नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने ठगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 15,000 म्यूल बैंक अकाउंट्स की पहचान की है। ऐसे कई अकाउंट्स को ऑपरेट करने वाले सात आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

सीआईडी की जानकारी के अनुसार, म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी की रकम जमा करने और अन्य अवैध लेनदेन के लिए किया जाता है। इस सिलसिले में जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, उससे इंटरस्टेट क्राइम लिंकेज का खुलासा हुआ है।

इनमें रौशन कुमार तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ऐसे खातों को ऑपरेट करता था। राजेंद्र साव दिल्ली में बैठकर साइबर ठगी को अंजाम देता था।

प्रेम रंजन सिन्हा आंध्र प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के लोगों को साइबर ठगी के जाल में फंसाता था। जितेंद्र कुमार पप्पू केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में सक्रिय था। नूरेज अंसारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल में अपराध करता था, जबकि सतीश कुमार आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सक्रिय था।

इसी तरह गणेश चिक बड़ाइक कर्नाटक, हिमाचल, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में लेनदेन और धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था।

बताया गया कि 10 लाख रुपए या उससे अधिक के लेनदेन वाले 40 खातों की पहचान करते हुए 29 जुलाई को पहली एफआईआर दर्ज की गई। जांच आगे बढ़ी तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की ओर से संचालित समन्वय पोर्टल के विश्लेषण के बाद 15 हजार म्यूल अकाउंट की पहचान हुई।

पकड़े गए आरोपी मुख्य रूप से निवेश घोटालों में शामिल थे और उनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। जांच अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े बैंक खातों और लेनदेन की कई शिकायतें बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में दर्ज हैं।

सीआईडी अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद निवेश घोटाले और साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है। म्यूल अकाउंट और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम में भी इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जांच अभी भी जारी है और अन्य संबंधित आरोपियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्रीमती साक्षी साहनी ने पराली को आग न लगाने के संबंध में जनजागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए जिला प्रशासन कार्यालय, अमृतसर से प्रचार वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

अमृतसर 21 अगस्त (साहिल बेरी)

उन्होंने बताया कि ये प्रचार वैनें अमृतसर जिले के सभी गांवों में जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पराली जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, जमीन की सतह को नुकसान पहुंचता है, मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं और बहुमूल्य पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पराली का उचित प्रबंधन करने वाले किसानों को 15 अगस्त के अवसर पर "किसान प्राथमिकता कार्ड" देकर सम्मानित किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं में लाभ प्रदान किया जाएगा।डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि इस वर्ष भी पराली का सही ढंग से प्रबंधन करने वाले किसानों को "हीरो किसान" के रूप में सम्मानित किया जाएगा तथा उन्हें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।इस अवसर पर श्री रोहित गुप्ता (अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर – जनरल), श्रीमती अमनदीप कौर (अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर – शहरी विकास) तथा रमन कुमार (डीडीओ, कृषि विभाग, अमृतसर) भी उपस्थित रहे।

आज से विधानसभा सत्र, 1000 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक रांची में आयोजित होने जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। विधानसभा (नया भवन) परिसर के चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 22 अगस्त सुबह 8 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

रांची उपायुक्त और जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि विधानसभा क्षेत्र के आसपास किसी भी तरह का जुलूस, धरना, रैली या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। पांच या पाँच से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे (सरकारी कामकाज और शवयात्रा को छोड़कर)। बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद जैसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला जैसे हरवे-हथियार पर रोक रहेगी। अगर किसी को कोई शिकायत या समस्या है तो वह रांची जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर – 9430328080 पर संपर्क कर सकता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023